

भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित

एजेंसी नई दिल्ली। लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन कर असम के गुवाहाटी में एक नया आईआईएम स्थापित करने और उसे अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रावधान है। इससे गुवाहाटी आईआईएम देश का 22वां आईआईएम बन जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन में विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विरोध दर्ज कराया। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना हो सकता है। हालाँकि सरकार की ओर से इस विषय पर विस्तृत उत्तर नहीं दिया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मदे प्रधान ने कहा कि यह विधेयक केवल शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा और प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक शुरुआत है। गुवाहाटी में आईआईएम की स्थापना की मांग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में साकार किया गया है। सरकार गुवाहाटी में आईआईएम की स्थापना के लिए 550 करोड़ रुपये की आर्थिक सहययता देगी और असम सरकार भूमि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ खान एवं खनिज संशोधन विधेयक

नई दिल्ली। राज्यसभा ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। यह विधेयक लोकसभा से 12 अगस्त को ही पारित हो चुका है। यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करेगा। विधेयक में प्रावधान है कि पट्टाधारक मौजूदा पट्टे में अन्य खनिजों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं। विधेयक पारित करने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को 11 बजे तक स्थगित कर दी गयी। सदन की कार्यवाही दोबारा दोपहर दो बजे शुरू होते ही पीठासीन सभापति घनश्याम तिवारी ने केन्द्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा के लिए नाम पुकारा। इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरेगे ने कहा कि विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। घनश्याम तिवारी ने कहा कि सदन में केवल विधायी कार्य ही होने चाहिए। इसके बाद विधेयक ने सदन से वॉकआउट किया। इस बीच खान मंत्री रेड्डी ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पर बहस शुरू की। इस विधेयक पर भाजपा सदस्य मयंक कुमार नायक (गुजरात), दीपक प्रकाश (झारखंड) और सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) तथा राकांपा सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने विधेयक के पक्ष में अपनी बात रखी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम की अंतरिम जमानत तीन सितंबर तक बढ़ाई

जोधपुर। रेप केस में सजा भुगत रहे आसाराम को गुजरात उच्च न्यायालय से एक बार फिर राहत मिली है। अदालत ने चौथी बार मेडिकल ग्राउंड पर तीन सितंबर तक अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने उसे 21 अगस्त तक और राजस्थान उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त तक की अंतरिम जमानत दी थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के ही आदेश पर सोमवार को आसाराम की अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल जांच हुई थी। इस दौरान अस्पताल में करीब दो घंटे तक अव्यवस्थाएं होने पर वहां मरीजों व परिजनों ने हंगामा किया था। आसाराम ने गुजरात उच्च न्यायालय से पूर्व में मिली अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने से पहले अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई हुई। इसमें आसाराम की ओर से अधिवक्ता ने आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की, जिनमें उसके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर बताई गई। इन्हीं के आधार पर गुजरात उच्च न्यायालय ने उसे राहत दी है।

दो माह तैयार हो जाएगा यूपी का पहला एसआईएचएम

गोरखपुर। प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (एसआईएचएम) दो माह में तैयार हो जाएगा। योगी सरकार द्वारा गोरखपुर में 48.39 करोड़ रुपये की लागत से बनवाए जा रहे एसआईएचएम के पहले फेज का 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया है। पर्यटन विभाग द्वारा अगले माह के अंत तक शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित किया गया है। बीते कुछ सालों में गोरखपुर का टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तेजी से आगे बढ़ा है। यहां कई बड़े ब्रांड के होटल्स, रेस्टॉरेंट खुल चुके हैं और कई खुलने की प्रक्रिया में हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कुशल पेशेवरों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (एसआईएचएम) बनवा रहे हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के कार्यालय के सामने बन रहे एसआईएचएम का निर्माण सितंबर माह तक पूरा हो जाएगा।

कोलकाता में शुरु होगा मेट्रो का नया अध्याय: प्रधानमंत्री मोदी देंगे 13.62 किमी की नई कनेक्टिविटी, दशकों की कमी को 10 साल में किया पूरा

एजेंसी कोलकाता। भारत की पहली मेट्रो सिटी कोलकाता अब सबसे तेजी से विस्तार पाता हुआ नेटवर्क बनने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस पूजा से पहले कोलकातावासियों को 13.62 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन का तोहफा देंगे। मेट्रो रेलवे ने मंगलवार शाम बयान जारी कर बताया कि तीन अहम रूट- ग्रीन लाइन (एस्प्लेनेड-सीलदह), येलो लाइन (नॉआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर) और ऑरेंज लाइन (हेमंत मुखोपाध्याय-बेलियाघाटा) यात्रियों के लिए खोले जाएंगे। इससे हवाइ मैदान से लेकर साइट लेट तक और दक्षिणेश्वर से लेकर दक्षिण कोलकाता के चपे-चपे तक महानगर कोलकाता मेट्रो से जुड़ जाएगा। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होना है। यह केवल बुनियादी ढांचे का विस्तार नहीं है बल्कि कोलकाता की जीवनशैली में बड़ा बदलाव लाने वाली पहल मानी जा रही है। दशकों से यातायात जाम, भीड़भाड़ और खासकर दुर्गा पूजा के

समय की अव्यवस्था झेलने वाले शहर के लिए यह नया नेटवर्क एक तरह का 'ल्योहरा तोहफ़ा' साबित होगा। 1984 से 2014: धीमी रफ्तार, 2014 के बाद तेज प्रगति रेलवे ने अपने बयान में बताया है कि कोलकाता ने 1984 में भारत की पहली मेट्रो सेवा शुरू कर देश को गौरव दिया था। लेकिन उसके बाद तीन दशकों तक पतवार बेहद धीमी रही। 1984 से 2014 तक केवल 27.99 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक बिछ पाया।वहीं, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 45 किलोमीटर नया नेटवर्क जुड़ा है, जो पिछले 30 साल के मुकाबले 161 फीसदी अधिक है। यही कारण है कि अब कोलकाता न केवल «पहली मेट्रो सिटी» कहलाता है बल्कि «सबसे तेजी से बढ़ता मेट्रो नेटवर्क» भी बनने की ओर है।ग्रीन लाइन (एस्प्लेनेड-सियादह) : यह रूट कोलकाता की दो अहम धड़कनों को जोड़ेगा। जहां पहले सड़क मार्ग से एक घंटे तक लगने थे, वहीं अब मेट्रो से सफर 11 मिनट में पूरा होगा।

एकत्र हो गए, जिससे ट्रेन का संचालन रोकना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में मछुआरों के एकत्र होने से प्रशासन व रेलवे अधिकारियों में हड़कप मच गया है। दउअसल, रामेश्वरम में मछुआरा संगठन श्रीलंकाई जेलों में बंद भारतीय मछुआरों की रिहाई और ज्वब उनकी नावों की वापसी की मांग को लेकर 11 अगस्त से

बादल फटने और भूस्खलन से निपटने की रणनीति तैयार की जा रही है :अमित शाह

एजेंसी नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार व्यापक रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में अब केवल राहत कार्यों पर निर्भर रहने के बजाय बचाव और रोकथाम को प्राथमिकता दी जा रही है। शाह यहां ‘आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण’ विषय पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार के अलावा समिति के सदस्य, केन्द्रीय गृह सचिव तथा एनडीएमए,



ने कहा कि 2014 से पहले आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण राहत-केंद्रित था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बचाव और रोकथाम-केंद्रित बनाया। उन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई

जनहानि में उल्लेखनीय कमी आई है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 1999 में ओडिशा चक्रवात में जहां 10,000 लोगों की जान गई थी, वहीं हाल के वर्षों में आए चक्रवात ‘बिपरजाय’ और ‘दाना’ में शून्य

छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल पांच दिनों की ईडी रिमांड पर

एजेंसी रायपुर। शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे आरोपित चैतन्य बघेल को विशेष अदालत ने पांच दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टोडियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। अब 23 अगस्त तक ईडी उनसे पूछताछ करेगी। इससे पहले सोमवार को उनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने पर उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया था। उस दौरान विशेष अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। साथ ही ईडी ने चैतन्य को कस्टडी में लेकर पूछताछ की मांग की थी, चैतन्य बघेल की रिमांड को लेकर एक बार फिर विशेष अदालतमें दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने चैतन्य बघेल को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में 23 अगस्त को चैतन्य बघेल की पेशी विशेष अदालतमें होगी। रिमांड मिलने के बाद अब



(ईडी) ने सोमवार को कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन पेश किया था, जिसकी बहस हुई है। इस दौरान परिवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि, ब्रह्म 187, 3 जो नया कानून आया है। 40 दिन की अवधि के बीच में 15 दिनों की कस्टोडियल रिमांड टुकड़े-टुकड़े में ली जा सकती है। बचाव पक्ष ने इस पर बहस की।

मध्य प्रदेश के दौरे पर आा जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने इंदौर में किया इनोवेशन लैब्स का भ्रमण

एजेंसी भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन देने के प्रयासों को नया आयाम मिला है। गुजरात इंस्टीटयल इवेस्टमेंट कार्पोरेशन के नेतृत्व एवं एमपीआईडीसी और आईएम ग्लोबल के सहयोग से जर्मनी की पाँच अग्रणी टेक कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम-2025 में शामिल हुआ।



प्रतिनिधिमंडल 22 अगस्त तक इंदौर और भोपाल के दौरे पर रहेगा। जर्मन दूतिनिधिमंडल ने अपने मध्य प्रदेश दौर के दूसरे दिन इंदौर में इनोवेशन लैब्स का भ्रमण किया, जहाँ उन्होंने एआई, डेटा एनालिटिक्स, आईओटी एवं एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर परियोजनाओं का

प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। शुरुआत डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप से हुई, जिसमें नवाचार एवं समस्या समाधान

यूपी सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यूके के बीच समझौता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उनके सरकारी आवास पर उ्तर प्रदेश सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ) यूके के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके तहत चिबनिंग-भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उ्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हर साल प्रदेश के पांच प्रतिभाशाली छात्रों को युनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार प्रतिभाशाली छात्रों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छात्रवृत्ति योजना प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने और युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का सशक्त माध्यम बनेगी।

पर इंटीरेक्टिव राउंडटेबल और द्विपक्षीय बैठकें एमपीआईडीसी में हुईं। एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक



आईएएस हिमांशु प्रजापति ने राउंडटेबल सत्र का नेतृत्व करते हुए कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय साझेदारी, तकनीकी सहयोग एवं एंटरप्राइज विकास में सक्रिय और प्रेरक भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि आज का

दिन मध्य प्रदेश और जर्मनी के प्रमुख आईए (टू) एवं ट्विक्झ इनोवेटर्स के बीच साझेदारी की गई शुरुआत का प्रतीक है। प्रजापति ने कहा कि समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि भारत में डेटा का डिजिटलीकरण अभी आरंभिक अवस्था में है, तथा डेटा की पुनरावृत्ति दीर्घकाल में दक्षता को प्रभावित करती है। इसी कारण भारत आज एआई और डेटा-आधारित प्रक्रियाओं के एकीकरण पर विशेष बल दे रहा है। ऐसे समय में आपका भारत आना अत्यंत अवसरपूर्ण है। प्रजापति ने यह भी विशेष रूप से रेखांकित किया कि इंदौर में ऑपरेटिंग कॉन्स्ट अन्य मेट्रो शहरों की तुलना में कहीं कम है, वहीं शहर की लिवेबिलिटी उद्यमियों और निवेशकों को यहाँ काम करने के लिए और भी आकर्षक बनाती है।

आपातकाल के दौरान 1.07 करोड़ से अधिक लोगों की नसबंदी की गई : केंद्र सरकार

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि वर्ष 1975 से 1977 के दौरान देश में लागू आपातकाल की अवधि में 1.07 करोड़ से अधिक लोगों की नसबंदी की गई, जोकि उस समय तय किए गए कुछ लक्ष्य से काफी अधिक थी। यह जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी।

तेलंगाणा से सांसद कॉन्डा विश्वेश्वर रेड्डी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने दो वर्षों 1975-76 और 1976-77 के लिए क्रमशः 24.85 लाख और 42.55 लाख नसबंदी प्रक्रियाओं का लक्ष्य तय किया था। हालांकि 1975-76 में 26,24,755 और 1976-77 में 81,32,209 नसबंदी सर्जरी की गई। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,07,56,964 नसबंदी हुई, जो कि



शाह आयोग के समक्ष 548 अविवाहित व्यक्तियों की नसबंदी और 1,774 मौतों के मामले, जो नसबंदी से जुड़े हुए थे, दर्ज कराए गए। उल्लेखनीय है कि 28 मई 1977 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. सी. शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया था, जिसे आपातकाल के दौरान हुए दुरुपयोगों और परिवार नियोजन

भारत ने चीन के साथ उठाया ब्रह्मपुत्र पर मेगा डैम का मुद्दा, पारदर्शिता पर दिया जोर

एजेंसी नई दिल्ली । भारत ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान ब्रह्मपुत्र (यारलुंग सांगपो) नदी के निचले हिस्सों में चीन की ओर से बनाए जा रहे मेगा डैम पर भी चिंता जताई है और कहा कि इससे निचले हिस्सों के भारतीय राज्यों पर गंभीर असर पड़ेगा। इस संबंध में अत्यधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि विदेश मंत्री जयशंकर के साथ वार्ता के दौरान चीन की ओर से ताइवान का मुद्दा उठाया गया। इस पर भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है और ताइवान के साथ उसके संबंधों में गंभीर आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक सीमित रहेंगे। भारत ने यह भी इंगित किया कि चीन स्वयं भी इन क्षेत्रों में ताइवान से सहयोग करता है। विदेश

मंत्रालय ने चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारत और चीन के बीच संबंधों को नई गति देने के प्रयास में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 18-19 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं वार्ता की सह-अध्यक्षता की और विदेश मंत्री डॉ एफ. जयशंकर से द्विपक्षीय वार्ता की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। मंत्रालय के अनुसार विशेष प्रतिनिधि वार्ता में तनाव कम करने, परिसीमान और सीमा मामलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा में साझा हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई।

आदि कर्मयोगी अभियान समावेशी शासन एवं जनभागीदारी को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम: जुएल ओराम

एजेंसी नई दिल्ली । केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान समावेशी शासन एवं जनभागीदारी को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सेवा, संकल्प एवं समर्पण को बढ़ावा देकर तथा जनजातीय समुदायों एवं सरकारी अधिकारियों के सहयोगात्मक भागीदारी के माध्यम से हम 1 लाख जनजातीय ग्राम-विजन 2030 का सह-निर्माण करेंगे।

जनजातीय कार्य मंत्रालय शुरू किए गए आदि कर्मयोगी अभियान की समीक्षा करते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि इस पहल में जमीनी स्तर पर जनजातीय विकास के लिए परिवर्तनकारी क्षमता है और यह मिशन मोड पर जनजातीय गांवों के समग्र विकास को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव विष्णु नायर ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान को जमीनी स्तर पर उत्तरदायी शासन को क्रियान्वित

करने के लिए तैयार किया गया है। शासन प्रक्रिया प्रयोगशालाओं के माध्यम से, सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों को प्रभावी परिवर्तन अग्रणी बनने के लिए संरचित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से



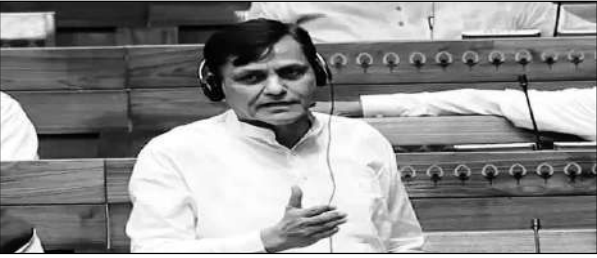
आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया है, जिसे विश्व के सबसे बड़े जनजातीय मूलभूत नेतृत्व कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना, उत्तरदायी शासन को मजबूत करना और पूरे देश में स्थानीय नेतृत्व के अवसरों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू किया

तमिलनाडु सरकार खर्च नहीं कर रही है पीएम आवास योजना की राशि: चौहान

एजेंसी रायपुर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में तमिलनाडु सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि खर्च नहीं करने का आरोप लगाते हुये कहा कि यह गरीबों के साथ धोखा है। श्री चौहान ने कहा का पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि केंद्र से 608 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद तमिलनाडु सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास उपलब्ध नहीं करा पा रही है। आवास नहीं मिलने से गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में आवंटन के बावजूद दो लाख 15 हजार घरों का निर्माण नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने 2024 में उचित घरों की जरूरत वाले लोगों की पहचान के लिए आवश्यक सर्वेक्षण नहीं कराया। आंध्र प्रदेश से तेलुगू देशम पार्टी(तेदेपा) सांसद लवू श्री कृष्ण देवरायलु द्वारा तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आवास योजना पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के लिए दायर कः- मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने तमिलनाडु में गरीब लोगों के लिए घर बनाने के लिए बजट आवंटित किया है। यह अन्याय की पराकाष्ठा है कि एक साल से भी ज्यादा समय से दो लाख 15 हजार से ज्यादा लोगों को घर नहीं दिये गये हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम आवास योजना के लिए जारी की गयी 608 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार के खाते में पड़ी है, लेकिन आवासों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है।

आपातकाल के दौरान 1.07 करोड़ से अधिक लोगों की नसबंदी की गई : केंद्र सरकार

कार्यक्रमों में की गई जबरन नसबंदी जैसे मामलों की जांच का दायित्व सौंपा गया था। शाह आयोग ने 31 अगस्त 1978 को संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की



थी, जिसमें राज्यवार आंकड़ों के साथ-साथ जबरन कराई गई नसबंदियों, मानवीय अधिकारों के उल्लंघन और प्रशासनिक दमन के मामलों का उल्लेख किया गया। आयोग के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 14.44 लाख, पश्चिम बंगाल में 10.86 लाख, उत्तर प्रदेश में 9.65 लाख, मध्यप्रदेश में 11.13 लाख, तमिलनाडु में 8.40

थी, जिसमें राज्यवार आंकड़ों के साथ-साथ जबरन कराई गई नसबंदियों, मानवीय अधिकारों के उल्लंघन और प्रशासनिक दमन के मामलों का उल्लेख किया गया। आयोग के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 14.44 लाख, पश्चिम बंगाल में 10.86 लाख, उत्तर प्रदेश में 9.65 लाख, मध्यप्रदेश में 11.13 लाख, तमिलनाडु में 8.40

हो गए। थंगाचिमादम में रेलवे ट्रैक पर मछुआरों के आ जाओ से रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कप मच गया। थंगाचिमादम में मछुआरों पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी मछुआरे श्रीलंकाई नौसेना के पकड़े गए अपने साथियों की रिहाई और ज्वब नावों की वापसी की मांग कर रहे थे।



रविवार को जिला मजिस्ट्रेट सिमरनजीत सिंह कालोन के साथ रामनाथपुरम में पहली और फिर सोमवार को कोल्लचियार राजमनोहरन के नेतृत्व में रामेश्वरम तालुक कार्यालय में दूसरे दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इससे नाराज मछुआरों ने रविवार दोपहर 3 बजे थंगाचिमादम में रेलवे ट्रैक पर एकत्र

एजेंसी रामेश्वरम। श्रीलंकाई जेलों में बंद मछुआरों की रिहाई और ज्वब नावों की वापसी की मांग को लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरा संगठन 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मछुआरे थंगाचिमादम में रेलवे ट्रैक पर

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मछुआरों ने 13 अगस्त को थंगाचिमादम में प्रदर्शन किया और 15 अगस्त को भूख हड़ताल रखी थी। मछुआरों की मांगों और उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई कदम न उठाने से नाराज मछुआरा संगठनों ने थंगाचिमादम में रेल हड़ताल करने का ऐलान किया था। इससे पहले

श्रीलंका में बंद साधियों की रिहाई के लिए थंगाचिमादम में रेलवे ट्रैक पर उतरे मछुआरे, रेल यातायात प्रभावित

मछुआरों ने रेलवे ट्रैक पर आ जाने के कारण रामेश्वरम-तांवरम एक्सप्रेस ट्रेन को थंगाचिमादम में रोक दिया गया है। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के मछुआरों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। किसी अनहोनी को रोकने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

विट्ठलभाई पटेल ने ‘मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ बनाने का काम किया: सीएम रेखा गुप्ता

एनसीआर समाचार

नई दिल्ली। विट्ठलभाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर बनने के 100 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली विधानसभा में दो दिवसीय शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि विट्ठलभाई पटेल ने ‘मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ बनाने का काम किया। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘आज का दिन हमारे लिए लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन है। 100 साल पहले इस विधानसभा



परिसर में ब्रिटिश काल में पहली बार कोई भारतीय मूल का व्यक्ति इस

विधानसभा का अध्यक्ष बना था। उस समय पहली लौ भारतीय के दिल में

जगी होगी कि इस ब्रिटिश काल में भी भारतीय अपनी आवाज उठा सकता

है और सदन पटल तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा, ‘विट्ठलभाई पटेल ने जरूर यह सोचा होगा कि जब एक दिन भारत आजाद होगा तब भारतीय आजाद भारत में अपने स्वराज के साथ, अपने झंडे तले, अपने संविधान की छाया में, अपने प्रदेश और देश का प्रतिनिधि बनकर ऐसी ही विधानसभा में बैठेंगे। वे देश की जनता की बेहतरी के लिए नीति का निर्माण करेंगे।’

उन्होंने कहा, ‘विट्ठलभाई पटेल के निर्णय की कोई भी आलोचना नहीं करता था। उन्होंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने का काम किया। उनके जीवन की गौरव गाथा की

प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है और उनके महत्वपूर्ण योगदान को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है।’

कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय गृहमंत्री सदन में लोकतंत्र की आवाज बनकर पेश होते हैं। उन्होंने लोकसभा सदन को नया मायना दिया है। वे मानसून सत्र में जो कानून लेकर आए हैं, वह पूरे सदन को उन कानूनों को बनाने की ताकत देता है कि जनता और देश के हित में निर्णय ले सकें और देश आगे बढ़े। अमित शाह लोकतंत्र की रक्षा में काम करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं।’

दिल्ली में बस रूट पुनर्निर्धारण की योजना अधर में, फंड की कमी बनी रोड़ा

एनसीआर समाचार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की बस रूट पुनर्निर्धारण योजना फिलहाल अधर में लटकी हुई है। परिवहन विभाग ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से तीन करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि की मांग की है। बिना फंड मिले यह योजना ठप पड़ी हुई है।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) ने पूरे शहर में बस रूटों के सर्वे और नए रूट तय करने का काम आईआईटी दिल्ली से कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए भुगतान परिवहन विभाग की सहयोगी संस्था डीटीआईडीसी (दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) के माध्यम



से किया जाएगा। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह का कहना है कि "इसमें कोई देरी नहीं है, सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जल्द ही फंड जारी कर दिया जाएगा और योजना पर काम शुरू होगा।" हालांकि, वर्तमान में स्थिति यही है कि फंड की कमी से योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन पहले से ही अव्यवस्थित है। एक

और बसों की संख्या कम है, वहीं दूसरी ओर रूट निर्धारण भी सही नहीं है। कई रूट ऐसे हैं जहां लोग घंटों तक बस का इंतजार करते हैं, जबकि कुछ रूटों पर एक साथ कई बसें पहुंच जाती हैं और वे खाली चलती हैं। इस असंतुलन से यात्री बेहद परेशान हैं।

पूर्व में हुए एक अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में करीब 37 प्रतिशत लोग सार्वजनिक परिवहन

का उपयोग करते हैं। यात्रियों की औसत यात्रा लंबाई 11.2 किलोमीटर है। आनंद विहार आईएसबीटी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कनॉट प्लेस, कश्मीरी गेट आईएसबीटी और बदरपुर जैसे ट्रॉजिट सेंटर्स पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बदरपुर बॉर्डर पर पीक आवर में प्रति घंटा 1382 लोग बसों में सफर करते हैं, जबकि कश्मीरी गेट पर यह संख्या 480, मंडी हाउस में 408, पालिका केंद्र में 380 और मंगलापुरी टर्मिनल पर 327 है।

यात्री संख्या और रूट की इस असमानता को दूर करने के लिए ही बस रूट पुनर्निर्धारण योजना बनाई गई थी, लेकिन अब फंड की कमी इसकी राह में सबसे बड़ी अड़चन बन गई है।

पांच करोड़ की हेरोइन के साथ दो महिला आरोपित गिरफ्तार



नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पांच करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ नशे के कारोबार में लिप्त दो महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली पुलिस ने सप्लाई चेन का पदार्फाश करते हुए नंद नगरी से महिला तस्कर सीमा और उसकी रिश्तेदार/सहयोगी समीता को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 1,049 ग्राम हेरोइन, एक स्कूटी, 22,900 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) यूनिट की टीम को सूचना मिली थी कि उत्तर पूर्वी जिले के इलाकों में मादक पदार्थों की बड़ी खेप सप्लाई की जा रही है। सूचना को पुष्टा कर पुलिस टीम ने 22 अगस्त को जीटीबी अस्पताल के पास जाल बिछाया और डी ब्लॉक, झुग्गी नंद नगरी इलाके में बात करने आई सीमा और समीता को गिरफ्त में लिया। वे एक नीली स्कूटी एक्टिवा पर सवार थीं, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया।

पुलिस जांच में पता चला है कि 54 वर्षीय सीमा पिछले 25 साल से नशे के कारोबार में सक्रिय हैं। उसके खिलाफ 10 मादक पदार्थों और 30 आबकारी एक्ट के मामलों में सजा हुई है। सीमा के परिवार के कई सदस्य, जिनमें उसके दो बेटे भी शामिल हैं, इस धंधे में सक्रिय हैं। पुलिस ने उसे पहले भी तड़ीपार किया था।

दिल्ली में पनीर खाने वाले रहें सावधान, नकली पनीर का कारोबार चरम पर

एनसीआर समाचार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नकली पनीर का कारोबार तेजी से पांव पसार रहा है। सस्ते दाम पर मिलने वाले पनीर व्यंजन लोगों को लुभा रहे हैं, लेकिन यह स्वाद सेहत पर भारी पड़ रहा है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में प्रतिदिन 30 टन से अधिक नकली पनीर की खपत हो रही है। अकेले सालाना खपत का आंकड़ा 1100 टन से ऊपर पहुंच चुका है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह नकली पनीर अधिकतर होटलों, ढाबों और फास्ट फूड स्टालों पर परोसा जा रहा है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद केंद्र सरकार को भी दखल देना पड़ा। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अप्रैल में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी ने भी एडवाइजरी जारी की। खाद्य सुरक्षा विभाग और एफएसएसएआई



लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कारोबार थमता नहीं दिख रहा। पिछले दिनों करावल नगर इलाके में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 600 किलो नकली पनीर जब्त किया गया था। यह पनीर अलीगढ़ से ट्रक भरकर दिल्ली के शाहदरा, सीलमपुर और पूर्वी दिल्ली के बाजारा में सप्लाई किया जाना था। दिल्ली के दूध कारोबारियों का कहना है कि असली पनीर बनाने के लिए जितना दूध चाहिए, वह उपलब्ध नहीं है। इसी कमी का फायदा उठाकर मेरठ, बुलंदशहर

और अलीगढ़ से नकली पनीर की सप्लाई बढ़े पैमाने पर की जा रही है। नकली पनीर बनाने में दूध की जगह वनस्पति तेल, पाम ऑयल, इमल्सीफायर और प्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। साइट्रिक एसिड या सिरके की मदद से इसे जमाकर ब्लॉक का आकार दिया जाता है। इसकी लागत बेहद कम—करीब 180 से 200 रुपये के लिए आती है, जबकि असली पनीर की कीमत 450 से 480 रुपये किलो है।

डॉक्टरों का कहना है कि इस

पेड़ों की छंटाई में निगम की लापरवाही, कोर्ट ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर पेड़ों की छंटाई में लापरवाही बरतने के आरोप एक बार फिर से सामने आए हैं। यमुनापार आर.डब्ल्यू.ए. और एम.डब्ल्यू.ए. के संस्थापक अध्यक्ष दीपक शर्मा का कहना है कि निगम अधिकारियों को बार-बार निवेदन करने के बावजूद समय पर छंटाई नहीं की जाती। इसके चलते न केवल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। दीपक शर्मा ने आरोप लगाया कि आर.डब्ल्यू.ए. और अन्य एसोसिएशन लगातार छंटाई की मांग करते रहते हैं, लेकिन निगम का रवैया ढीला है। उन्होंने कहा कि अब तो स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यह साफ दिखाता है कि निगम किस स्तर पर लापरवाही बरत रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। द्वारका

इलाके में पेड़ों की छंटाई न होने पर अदालत ने एमसीडी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि पैदल यात्रियों और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल छंटाई बेहद जरूरी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब एक जान जा चुकी है, तो निगम के लिए और क्या सबक हो सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर बारिश में पेड़ों के गिरने से जान-माल का नुकसान होता है, लेकिन विभाग समय रहते कदम नहीं उठाते। कोर्ट ने एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभागों को आदेश दिया कि द्वारका इलाके का 10 दिनों के भीतर सर्वे किया जाए और यह पता लगाया जाए कि किन पेड़ों की छंटाई की जरूरत है। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि सर्वे पूरा होने के चार हफ्तों के भीतर पूरी छंटाई का काम पूरा किया जाए।

एनसीआर समाचार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से अन्यत्र ले जाए जाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कुत्ता प्रेमियों और गैर सरकारी संगठनों से मामले में सुनवाई से पहले एक सप्ताह के भीतर क्रमशः 25,000 रुपये और दो लाख रुपये जमा करने को कहा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग संबंधित नगर निकायों के तत्वावधान में आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य सुविधाओं में किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘इस अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले प्रत्येक कुत्ता प्रेमी और प्रत्येक एनजीओ को सात दिन के भीतर इस अदालत



की रजिस्ट्री में क्रमशः 25,000 रुपये और दो लाख रुपये जमा कराने होंगे। ऐसा न करने पर उन्हें मामले में आगे शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" पीठ में न्यायमूर्ति सदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल हैं।

कई गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर 11 अगस्त को शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा पारित कुछ निर्देशों

पर रोक लगाने की मांग की थी। शुक्रवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने, राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से, विशेषकर बच्चों में रेबीज होने की खबरों पर 28 जुलाई को शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में अपना यह आदेश सुनाया।

पीठ ने कहा कि इच्छुक पशु व्यक्तियों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर 11 अगस्त को शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा पारित कुछ निर्देशों

टैग किया जाएगा और आवेदक को गोद दे दिया जाएगा। इसमें कहा गया है, ‘आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि गोद लिए गए आवारा कुत्ते सड़कों पर वापस न आए।"'

पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में आश्रय स्थलों से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने संबंधी 11 अगस्त के निर्देश में संशोधन किया और कहा कि उठाए गए कुत्तों का बंध्याकरण किया जाना चाहिए, और उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया था।

पीठ ने हालांकि कहा कि नगर निगम अधिकारी उस निर्देश का पालन करना जारी रखेंगे, जिसमें उन्हें दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाने और उनकी देखभाल करने को कहा गया है।

एक नजर

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान और रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य नेताओं ने रविवार को 'अरुण जेटली पार्क' में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा सांसद रामवीर सिंह वघुडी, बांसुरी स्वराज तथा दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) अध्यक्ष रोहन जेटली सपरिवार उपस्थित रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि विधि के क्षेत्र से लेकर संसद के सर्वोच्च मंच तक अरुण जेटली की अद्वितीय प्रतिभा, गहन विचारशीलता और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण सदैव अनुकरणीय रहेगा। उनकी प्रखर वाणी, स्पष्ट दृष्टिकोण और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी दूरदर्शिता, सिद्धांत और विचारधारा सदैव हमें जनसेवा और राष्ट्रनिर्माण के पथ पर मार्गदर्शित करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले अरुण जेटली ने आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने संगठन से लेकर संसद तक अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे ऐतिहासिक सुधार को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरुण जेटली का सरल व्यक्तित्व, दूरदृष्टि और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण हम सभी को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

न्यू अशोक नगर पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़, चार बाइक बरामद

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का पदार्फाश किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई चार मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान करण (22) और कैफ (21) के रूप में हुई है। दोनों पुरानी कॉडली के रहने वाले हैं। पुलिस पृष्ठताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे भीड़भाड़ वाले बाजारां और रिहायशी इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। चोरी की गई गाड़ियां वे पुरानी कॉडली की संकरी गलियों और स्मृति वन पार्किंग में खड़ी कर देते थे, ताकि किसी को शक न हो। कुछ दिनों बाद वे उन मोटरसाइकिलों को फिर से निकालकर बेचने की योजना बनाते थे। पूर्वी जिला डीसीपी अफिफ़ धानिया ने बताया कि इलाके में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। एसीपी कल्याणपुरी की देखरेख में एसएचओ न्यू अशोक नगर के नेतृत्व में बनी इस टीम ने आरोपियों को घर दबोचा। शुक्रवार को गश्त के दौरान दल्लुपुरा-नोएडा रोड पर पुलिस ने संधिध हालत में दो युवकों को काले रंग की मोटरसाइकिल पर आते देखा। तलाशी लेने पर पता चला कि वह बाइक चोरी की थी और न्यू अशोक नगर थाने में उसकी एफआईआर दर्ज थी। पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुरानी कॉडली और स्मृति वन की पार्किंग से तीन और मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। इनमें दो बाइक गाजीपुर पेपर मार्केट से और एक गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके से चोरी की गई थी। आरोपियों के पास नकली चाबियों का जखीरा मिला है, जिनसे वे गाड़ियों का लॉक खोलते थे। कई बार वे हैंडल लॉक तोड़कर भी वाहन चुरा लेते थे। पुलिस का कहना है कि इनसे और बरामदगियां होने की संभावना है तथा दोनों आरोपियों से पृष्ठताछ जारी है।

सड़क किनारे बोरे में मिली लड़की की लाश, पुलिस ने जांच तेज की

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिमी दिल्ली के डाबड़ी इलाके में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब सड़क किनारे एक बोरी से लड़की का शव बरामद हुआ। राहगीरों ने बोरी को संधिध हालात में पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही डाबड़ी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। आसपास के लोगों से पृष्ठताछ की जा रही है, ताकि मृतका के बारे में सुराग मिल सके। स्थानीय निवासियों ने आशंका जताई है कि लड़की की हत्या कहीं और कर उसे यहां बोरी में भरकर फेंक दिया गया है। पुलिस इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे आरोपी तक पहुंचा जा सके। डाबड़ी की इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। लोग समूहों में इस वारदात पर चर्चा करते नजर आए। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल, पुलिस इस मामले को हत्या का शक मानकर गंभीरता से जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर मामले का पदार्फाश किया जाएगा।

द्वारका पुलिस ने अपराधी सुरेंद्र कुमार उर्फ लाला को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की द्वारका जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। द्वारका पुलिस ने एक बार फिर अपनी सतर्कता और सक्रियता का परिचय देते हुए एक अपराधी, सुरेंद्र कुमार उर्फ लाला को गिरफ्तार किया है। सेक्टर-10 द्वारका के नए चौकी प्रभारी, सब-इंस्पेक्टर रजत मलिक और उनकी टीम ने यह उपलब्धि अपने कार्यभार सभालने के कुछ ही दिनों में हासिल की। इस ऑपरेशन में 14 वृद्ध अपराधों से जुड़े एक अपराधी को पकड़ा गया, जिनमें 8 सैनचिंग, 4 गैर-जमानती वारंट, 1 डीसीपी गैर-जमानती वारंट और धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही शामिल है।

दिल्ली मेट्रो में हंगामा: दो महिलाओं की मारपीट का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली मेट्रो में आए दिन कभी यात्रियों की बहस तो कभी अजीबोगरीब हदकतों के वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। रविवार को ऐसा ही एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दी। वीडियो में दोनों महिलाएं एक-दूसरे के बाल नोचतीं, थपड़-घुंसे बरसातीं और जोर-जोर से चीखती-चिल्लाती नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वहां मौजूद यात्री इस पूरे घटनाक्रम को रोकने के बजाय मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बनाने में जुटे रहे। इस दौरान एक अन्य महिला बीच-बचाव करने की कोशिश करती भी दिखाई दी, लेकिन झगड़ रही दोनों महिलाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने महिलाओं के इस व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि मेट्रो जैसी सार्वजनिक जगह पर इस तरह का हंगामा शर्मनाक है, वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसे मामलों में मेट्रो सुरक्षा कर्मी क्यों नजर नहीं आते।

संपादकीय

सांसदों से वसूली की जाए

लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। यानी संसद का मांसून सत्र समाप्त हो गया। यह संसद सत्र न भी होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई राष्ट्रीय नुकसान नहीं होता। हम यह बहुत भारी मन से लिख रहे हैं, व्यक्ति महसूस कर रहे हैं। हालांकि यह कहना देशहित में नहीं है, क्योंकि संसद हमारा सर्वोच्च और गरिमामय लोकतांत्रिक मंदिर है। बार-बार यह महज एक संसदों ने ही यह मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सदन के स्थगन से जितना आर्थिक नुकसान हुआ है, उतनी राशि सांसदों से ही वसूल की जाए। सांसदों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए। विपक्ष ने सत्र के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा जारी रखा, जबकि उन्हें भी जानकारी थी कि संसद के भीतर चुनाव आयोग पर बहस नहीं की जा सकती। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का संवैधानिक विशेषाधिकार है, लेकिन विपक्ष ने सदन के भीतर और बाहर लगातार हंगामा किया और उसे अपना संवैधानिक अधिकार बताया। उस संदर्भ में वह बार-बार दिवंगत नेता अरुण जेतली को उद्धृत करता रहा। यदि संवैधानिक अधिकार के कारण ही संसद को कार्यवाही बाधित होती रहे और अंततः उसे स्थगित करना पड़े, तो उसके नुकसान की भरपाई और क्या? यह कहना अईसय है कि सदन की कार्यवाही चलाना सत्ता पक्ष का दायित्व है। यह कथन तब सही है, जब कार्यवाही में विपक्ष भी लगातार भागीदार बने। अभी बहस और चर्चाएं संभव हैं, तभी विधेयकों पर सामूहिक चर्चा कर उन्हें पारित करना संभव है। कहने को लोकसभा में 12 बिल और राज्यसभा में 14 बिल पारित किए गए। उन्हें ‘हां’ अथवा ‘ना’ के ध्वनिमत से पारित कर लिया गया। उसके लिए संसद की क्या जरूरत है? ऑनलाइन गेमिंग सरीखे बिल, जो करीब 45 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है और करीब 20,000 करोड़ रुपए दांव पर हैं, बिना चर्चा के ही पारित कर लिए गए। इंडियन पोस्टर्स बिल 2025 और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नर्स बिल महत्वपूर्ण बिल थे, लेकिन वे भी बिना चर्चा के पारित कर लिए गए।

–ललित गर्ग–

लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान उसकी संसद होती है। संसद वह संस्था है जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्र की नीतियों, योजनाओं और कानूनों पर विचार-विमर्श करते हैं। यह वह सर्वोच्च मंच है जहाँ विभिन्न विचारधाराएं और दृष्टिकोण टकराते हैं और देशहित में समाधान निकलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भारतीय संसद की छवि हंगामे, तोड़फोड़, शोर-शराबे और गतिरोध का पर्याय बनती जा रही है। हाल ही में संपन्न मानसून सत्र इसकी बानगी था, जो आरंभ से अंत तक त्रासद हंगामे की भेंट चढ़ गया। यह सत्र बेहद निराशा एवं अफसोसजनक रहा, क्योंकि सरकार और विपक्ष में टकराव उग्र से उग्रतर हुआ। राज्यसभा में केवल 41.15 घंटे और लोकसभा में 37 घंटे काम हुआ। संवाद एवं सौहार्द की कमी दिखी, कई सवाल अथूरे रहे, जिनका जवाब देश जानना चाहता था। यहाँ दोनों पक्षों से ज्यादा समझदारी, सौहार्द और संतुलित नज़रिये की अपेक्षा थी, लेकिन देशहित को दोनों पक्षों ने नेस्तनाबूद किया। यह स्थिति केवल दुखद ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय भी है।

लोकसभा के मानसून सत्र के लिए कुल 120 घंटे चर्चा के लिये निर्धारित थे, लेकिन कार्यवाही मात्र 37 घंटे ही चल

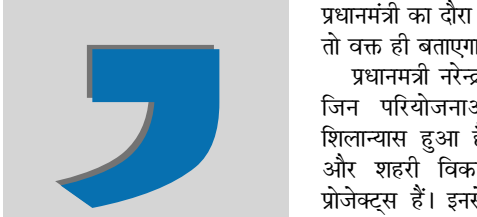
पाई। यानी 70 प्रतिशत से अधिक समय लोकसभा में और 61 प्रतिशत से ज्यादा समय राज्यसभा में हंगामे और शोर-शराबे की भेंट चढ़ गया। संसद में बिताया गया प्रत्येक घंटा जनता के करोड़ों रुपये की कमाई से संचालित होता है। जब वही समय व्यर्थ हो जाए तो यह सीधे-सीधे जनता के साथ अन्याय है। गुजरात के एक निर्दलीय सांसद ने यह प्रश्न उठाया भी कि जो सांसद हंगामा कर सदन को ठप कर देते हैं, क्या वे जनता के धन की बरबादी की भरपाई करेंगे? यह प्रश्न केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति हमारी गंभीरता की कसौटी भी है। काम कम, हंगामा अधिक-आखिर हमारे राजनीतिक दल एवं जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की मर्यादा एवं आदर्श को तार-तार करने पर क्यों तुले हैं? कैसी विडम्बना है कि लोकसभा की कार्यवाही के लिए 419 तारफिक प्रश्न शामिल किए गए थे और इनमें से महज 55 का मौखिक उत्तर मिल सका।

लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है और आवश्यक भी। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, सत्ता को जवाबदेह बनाना। लेकिन यह काम हंगामे, नारेबाजी और सदन की कार्यवाही बाधित करने से नहीं हो सकता। संसद संवाद का मंच है, न कि

मोदी का मिशन बिहार, सियासी जड़ें जमाने में जुटी भाजपा

–कुमार कृष्णन–

बिहार में बीजेपी का सबसे कमजोर गढ़ मगध का क्षेत्र माना जाता है, जिस पर अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए हरसंभव कोशिश में जुटी है। इस इलाके में भाजपा सियासी जुड़े जमाने के लिए जीवन राम मांझी, उपेन्द्र कुशवाहा और चिराम पासबान से हाथ मिलाकर रखा है। नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में महागठबंधन का ही पलड़ा भारी था। इस क्षेत्र की 20 सीट पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीट पर ही राजग को ही कामयाबी मिली थी।



संसद संवाद और बहस का मंच है, हंगामे का नहीं

संघर्ष का अखाड़ा। दुर्भाग्य यह है कि आज बहस और तर्क की जगह हंगामे और टकराव ने ले ली है। इससे न तो जनता की समस्याओं पर गंभीर विमर्श हो पाता है और न ही संसद की गरिमा सुरक्षित रह पाती है। सत्र शुरू होने के पहले कार्य मंत्रणा समिति में सरकार और विपक्ष के बीच कुछ मुद्दों पर चर्चा की सहमति बनी थी। लेकिन, सत्र शुरू होने के साथ ही उसे भुला दिया गया। संसदीय परंपरा में विरोध भी अधिकार है, लेकिन इसकी वजह से सदन की गरिमा और उसके कामकाज पर असर पड़ना दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिन्ताजनक है।

भारत का हर नागरिक संसद से अपेक्षा करता है कि वहां उसकी समस्याओं पर चर्चा होगी-बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दे प्राथमिकता पाएंगे। लेकिन जब टीवी स्क्रीन पर वह अपने प्रतिनिधियों को मेज थपथपाते, नारे लगाते और वेल में जाकर हंगामा करते देखता है तो उसका विश्वास टूटता है और मन आहत होता है। उसे लगता है कि जिन नेताओं को उसने वोट देकर भेजा था, वे उसके हितों की बजाय केवल राजनीति का खेल खेल रहे हैं। यही कारण है कि आज लोकतंत्र के प्रति आम नागरिक का मोहभंग बढ़ रहा है। वैसे भी यह मानसून सत्र ऐसे वक्त हो रहा था, जब

भारत नई चुनौतियों से गुजर रहा है। विदेश और आर्थिक, दोनों मोर्चों पर हालात तेजी से करस्ट ले रहे हैं। ऐसे में और भी अहम हो जाता है कि संसद में इस पर सार्थक चर्चा होती और वाद-विवाद से रास्ता निकाला जाता। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन-एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर पर कई सवाल बचे रह गए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के सजा की स्थिति-यानी जेल में होने पर पद से हटाने वाले संविधान संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस गंभीरता की जरूरत थी, वह नहीं दिखी।

संसद में हंगामे की प्रवृत्ति में केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भी अक्सर इसमें बराबर का भागीदार होता है। जब कोई दल विपक्ष में होता है तो वह विरोध के लिए हरसंभव कदम उठाता है, और जब वही दल सत्ता में आता है तो संसद की गरिमा की दुहाई देने लगता है। यह दोहरा रवैया लोकतंत्र को कमजोर करता है। संसद को सुचारुरूप से चलाना केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। दोनों पक्षों को यह समझना होगा कि वे जनता के सेवक हैं, और जनता उनके कामकाज पर पैनी नजर रखती है। संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए कठोर नियमों

ताकत मिलेगी, और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज यहां अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी हुआ है। अब बिहार के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए एक और सुविधा मिल गई है। गरीब के जीवन से मुश्किलें दूर करना, महिलाओं के जीवन को आसान बनाना सरकार का लक्ष्य है। जनता-जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशहाली होती है।

सरकार की प्रतिवद्धता दुहराते हुए कहा कि—मेरा एक बड़ा संकल्प है। जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा महत्वपूर्ण है। बोध गया से बेगूसराय तक विकास की सीगात देकर मगध से मुंगेर तक साधने की कोशिश की।

बिहार में बीजेपी का सबसे कमजोर गढ़ मगध का क्षेत्र माना जाता है, जिस पर अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए हरसंभव कोशिश में जुटी है। इस इलाके में भाजपा सियासी जुड़े जमाने के लिए जीवन राम मांझी, उपेन्द्र कुशवाहा और चिराम पासबान से हाथ मिलाकर रखा है। नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में महागठबंधन का ही पलड़ा भारी था। इस क्षेत्र की 20 सीट पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीट पर ही राजग को ही कामयाबी मिली थी। मगध और मुंगेर प्रमंडल में महागठबंधन कि दबदबा रहा है। इसे तोड़ने प्रधानमंत्री का दौरा कितना कारगर होगा, यह तो वक्त ही बताएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को मदद मिलेगी, और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज यहां अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी हुआ है। अब बिहार के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए एक और सुविधा मिल गई है। गरीब के जीवन से मुश्किलें दूर करना, महिलाओं के जीवन को आसान बनाना सरकार का लक्ष्य है। जनता-जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशहाली होती है।

मौर्य और चाणक्य की धरती है। जब-जब किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। बिहार की धरती पर लिया हुआ हर संकल्प, ये धरती की ताकत है, इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता।

उन्होंने कहा कि बिहार का तेज विकास केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज बिहार चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पिपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में पुरानी समस्याओं के समाधान तलाश गए हैं, और नई प्रगति के रास्ते भी बनाए गए हैं। आप याद करिए, लालटेन राज में यहाँ कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में ये क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना-जाना मुश्किल था। गयाजी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गाँव ऐसे थे, जहां बिजली के खंबे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था, बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। बिहार के लोगों को आरजेडी और उसके साथी सिर्फ अपना दुर्दैवक मानते हैं, उन्हें गरीब से सुख-दुःख, गरीब के मान-सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोये पड़े थे।

बिहार की राजग सरकार, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इन नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे-बेटी को

यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां-बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अब बिहार में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। गयाजी जिले के डोभी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो रहा है। गयाजी में एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। आज ही यहां बक्सर थर्मल पावर प्लांट का शुभारंभ भी हुआ है। कुछ ही महीने पहले मैंने औरंगाबाद में भी नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। भागलपुर के पीरपैती में भी नया थर्मल पावर प्लांट बनेगा। इस पावर प्लांट्स से बिहार में बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी। और आप सब जानते हैं, जब बिजली उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है? घरों में बिजली की सप्लाई बढ़ती है, और उद्योगों को भी ज्यादा से ज्यादा बिजली मिलती है। और इससे भी रोजगार के नए मौके बनते हैं। बिहार के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए नीतीश जी ने बड़ा अभियान चलाया हुआ है। ये नीतीश जी हैं, तभी यहां शिक्षकों की भर्ती भी पूरी पारदर्शिता से हुई।

यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार में ही रोजगार मिले, उन्हें नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े, इसमें केंद्र सरकार का एक नई योजना से भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अभी पिछले सप्ताह, इस 15 अगस्त से ही देशभर में प्रधानमंत्री विकासत भारत रोजगार योजना लागू हुई है। इसके तहत, हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे, तो केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी। जो प्राइवेट कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी, उन्हें भी अलग से पैसे सरकार देगी। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ बिहार के मेरे युवाओं को भी होगा।विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का

बांध विरोध के चालीस साल

–रेहमत–

'नर्मदा बचाओ आंदोलन' अपने चार दशकों के सफर में सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, सही जल-प्रबंधन, आदिवासी-किसानों-महिलाओं के सशक्तिकरण और मानवाधिकारों की लड़ाई का एक जीवंत प्रतीक बना है। दुनिया में कम लोग हैं जो सरकारी दमनचक्र और उपेक्षा के बावजूद टूटे नहीं और संघर्ष की जलती मशाल अपनी अगली पीढ़ियों को सौंपते रहे।

नर्मदा घाटी की तीन पीढ़ियों ने सामाजिक न्यालय और पर्यावरण संरक्षण की एक लौ को बड़ी शिद्वत से जलाए रखा है। करीब 40 बरस में मशाल बन चुके 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' का सफर छोटा नहीं है। 'सरदार सरोवर बांध' की मुखालिफत से शुरू हुई इस लड़ाई के पहले पर्यावरण शब्द नया था, हालांकि इसे लेकर 'मूलशीर्ष बांध विरोध,' 'चिपको आंदोलन,' 'सेव सायलेंट वेली' और 'मिट्टी बचाओ अभियान' जैसे आंदोलन अपनी छाप छोड़ चुके थे। 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' ने 'सरदार सरोवर' से प्रभावित होने वाले निमाड-मालवा के आदिवासी-किसानों के पुनर्वास और वित्तीय मामलों के साथ प्रभावितों की रोजी-रोटी, उपजाऊ खेती और जंगलों के विनाश का मामला भी उठाया था। आंदोलन की सक्रियता के कारण विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय नजरिए से भी देखा-परखा जाने लगा।

आंदोलन के प्रभाव क्षेत्र में लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए और उन्होंनेविस्थादन के अलावा अन्य मामलों को भी उठाया। यह सिलसिला अभी भी जारी है। 'सरदार सरोवर' के संघर्ष से प्रेरणा लेकर नर्मदा घाटी के ही 'बरगी,' 'भीमावद्र,' 'ईंदिरा सागर,' 'औकरेश्वरगढ़,' 'महेश्वरग,' 'अपर वेदा,' 'लोअर गोई,' 'मान,' 'जोराट' आदि बांधों के प्रभावित अपने अधिकारों के लिए खड़े होते गए और 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' का हिस्सा बने। ऐसे संघर्ष देश के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दिए। यह एक आंदोलन के जनांदोलन बनने का उदाहरण है।

'नर्मदा बचाओ आंदोलन' का केन्द्रो पश्चिमी मध्यप्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र और पूर्वी गुजरात का पहाड़ी आदिवासी इलाका और मैदानी निमाड इलाके का ग्रामीण अंचल रहा है। इन इलाकों में आमतौर पर महिलाओं की भागीदारी कम दिखाई देती है, लेकिन आंदोलन ने वैचारिक और रणनीतिक वजहों से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। नतीजे में सार्वजनिक कार्यक्र मों में आधी से अधिक संख्यामें में महिलाएं दिखाई देती रही। महिलाओं की यह भागीदारी केवल सार्वजनिक प्रदर्शनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे निर्णय प्रक्रिया में भी हिस्सा लेती थीं। आंदोलन के माध्यम से हुआ महिला सशक्तिकरण घरेलू मामलों से लेकर गांव-समाज में भी दिखाई दिया।

प्रभावितों की लड़ाई केवल नागरिकों के हकों की उपेक्षा करने वाली सरकारों के विरोध तक सीमित नहीं थी। 'सरदार सरोवर परियोजना' के लिए 45 करोड़ डॉलर का कर्ज देने पर विश्व बैंक को भी नर्मदा घाटी में विनाश का निमोहर उठहराया गया और अंततः उसे पीछे हटना पड़ा। पर्यावरण और पुनर्वास संबंधी चिंताओं के कारण विश्व बैंक द्वारा 'सरदार सरोवर परियोजना' की आर्थिक मदद रोकना एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय घटना और आंदोलन की जीत थी। तब तक कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला था जिसमें विश्व बैंक ने कभी किसी परियोजना से अपना हाथ खींचा हो।

जो चिंताएं भारत की बांध परियोजना में देखी गईं, वे ही दुनिया की अन्य बांध परियोजनाओं में भी थीं। इसलिए आंदोलन ने सम-विचारी समूहों के साथ मिलकर विश्व बैंक को बाध्य किया कि वह अपनी मौजूदा कर्ज नीति में बदलाव करे, ताकि दुनिया में कहीं भी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विनाश को रोका जा सके। विश्व बैंक को इसके लिए राजी होना पड़ा और 'इंटरनेशनल यूनिवन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर' (अड्यूसीपीएन) के साथ मिलकर बड़े बांधों के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों की समीक्षा हेतु 'विश्व बांध आयोग' का गठन करना पड़ा। इसमें आंदोलन की ओर से मेधा पाटकर को आयुक्त के रुप में शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका के जल-संसाधन मंत्री कादर अस्माल की अध्यक्षता वाले 'विश्व बांध आयोग' की रिपोर्ट के बाद विश्व बैंक को अपनी कर्ज नीति में बदलाव करना पड़ा और उसने कई सालों तक बांध परियोजनाओं को कर्ज देना बंद रखा। आंदोलन ने ऐसी सरकारें देखी हैं जिन्होंने प्रभावितों के जीवन, रोजी-रोटी और अधिकारों की लड़ाई को खालिज किया था। कुछ सरकारों ने आंदोलनकारियों के खिलाफ दमनचक्र भी चलाया, लेकिन जिन सरकारों ने उपेक्षा नहीं की, वे भी प्रभावितों को उनके अधिकार देने में अनिच्छुक ही रहें।

–तनवीर जाफरी–

बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व की इस्राईल सरकार ने अगस्त 2025 की प्रारंभ में फिलिस्तीन के गजा शहर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की योजना को मंजूरी देने तथा इस्राईल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गत 8 अगस्त को इस योजना को अनुमोदित करने के बाद गजा में नये सिरे से सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। "गिडियन्स चैरियट्स क्क" नाम की इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिये इस्राईल ने लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया है जबकि 20,0०0 सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाई गयी है। इस कार्रवाई को गजा शहर पर हमले के पहले चरण की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस्राईली योजना के अनुसार इस कार्रवाई में उत्तरी गजा से हजारों फिलिस्तीनियों को दक्षिण की ओर विस्थापित किया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ इस्राईल की सेना (आईडीएफ) गजा सिटी के बाहरी इलाकों में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि इस्राईल सरकार द्वारा इस कार्रवाई का मकसद हमاس को पूरी तरह से हथियारों से मुक्त करना,उपेक्षे नेताओं को गजा से निर्वासित करना, हमاس द्वारा बंधक बनाये गये शेष लोगों को मुक्त कराना तथागजा पट्टी को पूरी तरह से हथियार-मुक्त बनाना बताया

जा रहा है। परन्तु विश्व इसे गजा पर कब्जे के इस्राईली दुष्प्रयास के रूप में देख रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने इस कार्रवाई को अवैध कब्जा बताते हुये इसे तुरंत रोकने की मांग की है जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे "अपमानजनक" बताते हुये कहा है कि यह कार्रवाई गजा पर इस्राईली सैन्य कब्जे को मजबूत करेगी। इस्राईल के सहयोगी देश अमेरिका व ब्रिटेन सहित अन्य देशों ने भी इस्राईल की इस कार्रवाई को अवैध बताते हुये इसपर गहरी चिंता जताई है। परन्तु इस्राईल की नेतन्याहू सरकार पूरे विश्व की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुये गजा पर सैन्य नियंत्रण कर अपने इस अवैध कब्जे के मिशन पर आगे बढ़ती जा रही है। इस योजना के अंतर्गत इस्राईल, गजा पर प्रमुख सुरक्षा नियंत्रण रखेगा, जिसमें सीमाओं, हवाई क्षेत्र और समुद्री पहुंच शामिल है।

उधर इस्राईल की सेना में भी इस योजना पर एक राय नहीं है। आईडीएफ के ही कई वरिष्ठ अधिकारी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका मत है कि यह योजना जहां पहले से ही युद्ध से जूझ रहे आईडीएफ के सैनिकों को थकाने वाली साबित हो सकती है वहीं इससे इस्राईल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग भी पड़ सकता है। केवल नेतन्याहू ही इस कार्रवाई में इस्राईली दुष्प्रयास के रूप में देख रहा है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों में इस कार्रवाई को अतिवाधियों के मध्य राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों में इस योजना को गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने और फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को नष्ट करने का प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यूएन रिपोर्ट्स में इसे मानवीय आपदा बताया रहा है। क्योंकि इससे न केवल बड़ी संख्या में विस्थापन बढ़ेगा बल्कि इनमें काफी लोगों की मौत भी हो सकती है और यह गजा के बुनियादी ढांचे की तबाही भी बढ़ा सकता है। हमاس ने तो तो इसे "नरसंहार" बताते हुये कहा है कि इससे युद्ध और भी लंबा चलेगा। जबकि फिलिस्तीन इसे इस्राईल की "विस्तारवादी" नीति के रूप में वर्णित कर रहा है जो वेस्ट बैंक में नए बस्तियों से जुड़ी हुई है।

गौर तलब है कि गजा सिटी में लगभग 5 लाख से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं जो हमاس के विरुद्ध की जा रही इस्राईली सैन्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पहले से ही भुखमरी और विस्थापन जैसे मानवीय

संकट से जूझ रहे हैं। अब तो इस इलाके में अकाल के हालात बन चुके हैं। परन्तु इन्हीं हालात के बीच इस्राईल के रक्षा मंत्री इस्राईल काल्ज ने यह धमकी भी दे दी है कि यदि हमاس ने हथियार छोड़ने और सभी बंधकों की रिहाई की शर्त नहीं मानी तो पूरे गजा शहर को 'तबाह' कर दिया जाएगा। गजा पर सैन्य नियंत्रण को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही आलोचना और देश के भीतर ही इस योजना के भारी विरोध के बीच इस्राईल के रक्षा मंत्री द्वारा 'गजा शहर को तबाह कर देने' जैसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने का सीधा सा अर्थ है कि गजा को लेकर इस्राईल सरकार की संशा ठीक नहीं है। पहले भी इस्राईल की सैन्य कार्रवाइयों में फिलिस्तीन के रफाह और बेत हनून जैसे शहर बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। इस समय केवल गजा पट्टी में ही पांच लाख से अधिक लोग भुखमरी, अभाव और मौत जैसी भयावह परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। गजा की लगभग एक तिहाई आबादी अर्थात लगभग 6 लाख 41 हजार लोग मानवीय संकट जैसे भयानक हालात का सामना कर सकते हैं।अनुमान है कि इन विषम परिस्थितियों में जून 2026 तक पांच साल

से कम उम्र के 1.32 लाख बच्चों की जान 'खतरे' में पड़ सकती है। गजा में हमास इन्हीं हालात के बीच इस्राईल के अनुसार सात अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक यहाँ 62,192 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि "भुखमरी और कुपोषण" से गजा में अब तक 271 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 112 बच्चे शामिल हैं।

इन भयावह परिस्थितियों के मध्य इस्मइल की नेतन्याहू सरकार द्वारा बंधकों की रिहाई व हमास के निशर्यीकरण के नाम पर गजा पर बलात कब्जे का प्रयास और गजा शहर को 'तबाह' करने जैसी धमकी देना एक बार फिर इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पहले से ही फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा जमाये बैठा इस्राईल न केवल अपनी विस्तारवादी नीति पर अमल कर रहा है बल्कि 'ग्रेटर इस्माईल' के निर्माण के अपने दूरगामी लक्ष्य पर भी इसी रास्ते से आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ईरान ने इसी इस्राईल को सबक सिखाया था और जब इस्राईल को ईरान की सैन्य कार्रवाई से अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराते दिखाई देने लगा था तो आनन फानन में युद्धविराम के लिये राजी हो गया था।

आवश्यक सूचना

एनसीआर समाचार के समस्त पाठकों तथा पत्र के साथ जुड़े समस्त पत्रकारों, व्यावसायिक संयोजक, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/संस्थानों को यह सूचित किया जाता है कि गत वर्षों से श्री बलवीर सिंह के नेतृत्व व स्वामित्व में चले आ रहे वर्तमान एनसीआर समाचार पत्र का प्रकाशन व स्वामित्व मो. हनीफ, पुत्र श्री इस्माईल खान मास्टरजी, संगम विहार के स्वामित्व व नेतृत्व में हो रहा हैं। अतः भविष्य में समस्त प्रकार की व्यावसायिक, कानूनी एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु मो. हनीफ/ नये कार्यालय जी 12/276, संगम विहार, नई दिल्ली – 110062, दूरभाष (मोबाईल) 8888883968, 9811111715 से सम्पर्क करें

टोल प्लाजा कर्मियों ने कहासुनी पर सेना के जवान से की मारपीट, वीडियो वायरल

मेरठ (एजेंसी)। यूपी के मेरठ के टोल प्लाजा पर एक मारपीट का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो सररूपर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। आरोप है कि यहाँ टोल कर्मियों ने एक सेना के जवान के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला रविवार रात का मेरठ के सररूपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा का है। यहाँ पास के ही एक गांव का रहने वाले कपिल सेना में पदस्थ है। उनकी तेनाती जम्मू-कश्मीर में है। बताया जाता है कि कपिल कार से अपने दोस्त के साथ दिल्ली जा रहा थे और जब वह करनाल हाइवे पर भूनी टोल प्लाजा पर पहुंचे तो टोल पर जाम और टोल फौस को लेकर टोलकर्मियों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया जिसके बाद टोल कर्मियों ने सेना के जवान की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवान की लात, घुसों और डंडे से पिटाई की जा रही है। वहीं, इस दौरान एक टोलकर्म ने तो मारने के लिए ईंट उठा रखी है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ देर बाद कपिल पक्ष के लोग भी पहुंच गए और जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली में डीपीएस समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए भवन

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी और आनन फानन में स्कूलों को खाली कराया गया। जानकारी के मुताबिक जिन स्कूकों को बम की धमकी दी गई है उनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्रीराम वर्ल्ड स्कूल और मॉडर्न स्कूल शामिल हैं। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते के साथ दमकल विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। एहतियातान स्कूलों को खाली कराकर सभी छात्रों को वापस घर भेज दिया गया है। बता दें कि स्कूल-कॉलेजों को बम की धमकी मिलने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इस साल अब तक कई बार दिल्ली समेत देशभर के कई स्कूल-कॉलेज और हवाईअड्डों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि, हर बार यह धमकी महज अफवाह ही साबित हुई है दिल्ली पुलिस के अनुसार, दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) द्वाराका, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल और सेक्टर 10, द्वाराका स्थित श्रीराम वर्ल्ड स्कूल को एक ईमेल आईडी के जरिये धमकी मिली। सुरक्षा उपाय के तौर पर, स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते के साथ दमकल विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की टीमें सभी स्कूलों में गहनता से तलाश जारी है हालांकि पिछली दो बम धमकियां अफवाह निकलीं, सुरक्षा एजेंसियां आज की सूचना को गंभीरता से ले रही हैं और सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं। अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।

गुजरात में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आप तैयारियों में जुटी

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) तैयारियों में जुट गई है। गुजरात में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच आप गुजरात के सभी पंचायत और निकाय चुनावों को पूरे दमखम से लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी ने सोमवार को राज्य में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सभी पंचायतों और निकायों में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। गुजरात में आप के प्रदेश अध्यक्ष इशुदान गढ़वी ने प्रदेश के युवाओं को उम्मीदवार बनने के लिए आमंत्रित किया है।

टोल प्लाजा कर्मियों ने कहासुनी पर सेना के जवान से की मारपीट, वीडियो वायरल

मेरठ (एजेंसी)। यूपी के मेरठ के टोल प्लाजा पर एक मारपीट का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो सररूपर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। आरोप है कि यहाँ टोल कर्मियों ने एक सेना के जवान के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला रविवार रात का मेरठ के सररूपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा का है। यहाँ पास के ही एक गांव का रहने वाले कपिल सेना में पदस्थ है। उनकी तेनाती जम्मू-कश्मीर में है। बताया जाता है कि कपिल कार से अपने दोस्त के साथ दिल्ली जा रहा थे और जब वह करनाल हाइवे पर भूनी टोल प्लाजा पर पहुंचे तो टोल पर जाम और टोल फौस को लेकर टोलकर्मियों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया जिसके बाद टोल कर्मियों ने सेना के जवान की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवान की लात, घुसों और डंडे से पिटाई की जा रही है। वहीं, इस दौरान एक टोलकर्म ने तो मारने के लिए ईंट उठा रखी है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ देर बाद कपिल पक्ष के लोग भी पहुंच गए और जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लोगों से लाखों की धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले छह साइबर आरोपी गिरफ्तार

नूंह (एजेंसी)। हरियाणा के नूंह जिले में तीन अलग-अलग मामलों में लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने छह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक दो भाइयों को नटराज पेंसिल कंपनी के नाम पर घर बैठे काम दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन मोबाइल फोन पर दोनों भाइयों ने राजीव सिंह और पूजा खेदी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखे थे। एक अन्य मामले में, फिरोजपुर बाहर गांव के एक अन्य आरोपी को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है।

उपराष्ट्रपति के पद पर राधाकृष्णन की जीत लगभग तय, विपक्ष के लिए खड़ी हुई चुनौतियां

नई दिल्ली (एजेंसी)। अगले माह 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। वोटों की संख्या के आधार पर माना जा रहा है कि राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है। इसके बाद भी विपक्ष संभवता अपना उम्मीदवार उतार सकता है। इससे पहले विपक्षी गठबंधन के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। एनडीए का कहना है कि विपक्ष से बात करके उनका समर्थन मांगे। कोशिश करेंगे कि चुनाव निर्विरोध हो जाए।

वहीं जानकारी का मानना है कि एनडीए के इस दांव से विपक्षी दलों के सामने कुछ चुनौतियां जरूर खड़ी हुई हैं। खासतौर से तमिलनाडू में डीएमके के लिए। जहां ओबीसी के नेता का विरोध करना इनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी तरह दूसरे दलों को भी विरोध करने में ओबीसी फैक्टर दिक्कत खड़ी कर सकता है। वहीं सूत्रों के अनुसार, रक्षा मंत्री



राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को कॉल कर एनडीए के उपराष्ट्रपति

उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा है। एनडीए के नेताओं ने खुलकर समर्थन

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी, 11 जिलों में हाई अलर्ट जारी

– प्रशासन ने नहरों, नालों और पुरानी इमारतों के आसपास न जाने की दी हिदायत

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। प्रशासन ने अगले 56 घंटे तक हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके चलते जम्मू संभाग में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं वैष्णो देवी यात्रा भी रोक दी है और पहाड़ी इलाकों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंधित लगा दिया है। प्रशासन ने नहरों, नालों और पुरानी इमारतों के आसपास न जाने की सख्त हिदायत दी है। निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है।

मौसम विभाग ने जम्मू संभाग और कश्मीर के 11 जिलों जिसमें जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रामन और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमों को अलर्ट पर रखा है। बता दें रविवार सुबह कठुआ जिले में तीन जगह बादल फटने की घटनाएं हुई थीं, जोद घाटी में सात लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं।

पुलिस के मुताबिक लैंडस्लाइड से दो



से तीन घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। हाईवे और रेलवे ट्रैक भी जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हैं। 14 अगस्त को किश्तवाड़ के चलोटी गांव में भी बादल फटने से तबाही मची थी। इस घटना में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू

किया गया है जबकि 180 घायल हैं।

कठुआ और किश्तवाड़ में सेना और

राहत एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं।

एनडीआरएफ की तीन टीमें, सेना के 300 से ज्यादा जवान, पुलिस और एसडीआरएफ के साथ मिलकर मलबा हटाने और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम कर रहे हैं। घायलों को जम्मू और किश्तवाड़ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। चलोटी गांव में हालात इतने भयावह हैं कि लोग प्रशासन पर नाराजगी जता रहे हैं।

उत्तराखंड में आसमान से उतरी तबाही की बारिश-सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे, गंगोत्री हाईवे बंद

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से हो रही बारिश आफत बन गई है। द्वितीय केदार मघाहेश्वर पैदल मार्ग बनतोली के पास भूस्खलन से लगभग 50 मीटर ख्वस्त हो गया, जिससे मघाहेश्वर लौट रहे सैकड़ों तीर्थयात्री मार्ग में फंस गए। सूचना मिलते ही एएसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे यात्रियों को सुरक्षित दूसरी तरफ लाया जा रहा है। वहीं, रिश के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी जगह-जगह भूस्खलन और भूधंसाव हुआ है।

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि पैदल मार्ग में करीब 200 यात्री फंसे थे, जिन्हें रेस्क्यू टीमों द्वारा सुनिश्चित की। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के हटाने का काम रविवार देर रात तक जारी रहा

केशव प्रसाद मोर्य ने कांग्रेस को दिखाया आईना, राहुल गांधी का व्यवहार पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए वोट चोरी आरोप को बेतुका बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सैवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर देश में अराजकता फैला रहे हैं। रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी को हलफनामा देने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम देने पर उपमुख्यमंत्री मोर्य ने बिलकुल सही बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी सैवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, वहां कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि हर काम करने की एक तय प्रक्रिया होती है। अगर किसी राजनीतिक दल को मतदाता सूची प्रकाशन और संशोधन पर आपत्ति है, तब वह आधिकारिक तौर पर उठा सकता है। लेकिन, राहुल गांधी देश में अफवाहें फैला रहे हैं। उनका आचरण न लोकतांत्रिक है और न ही सैवैधानिक, बल्कि राहुल गांधी का व्यवहार पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की हरकतें निंदनीय हैं। एनडीए द्वारा महापट्ट के राज्यापाल सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं और राधाकृष्णन को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आदिवासी समुदाय से एक राष्ट्रपति मिला है और अब ओबीसी वर्ग से एक उपराष्ट्रपति होगा। यह बहुत बड़ा संदेश है, वहां दक्षिण भारत से आते हैं। एनडीए ने जो फैसला लिया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं।

विदेश में बैठकर कई गैंगस्टर देश में करवा रहे है हत्याएं और जबरन वसूली

–तीन बड़ी घटनाओं के बाद पुलिस की कार्यशैली और मुखबिर तंत्र पर उठ रहे सवाल

गुरुग्राम (एजेंसी)। विदेश में बैठे कई बड़े गैंगस्टर इन दिनों गुरुग्राम पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। देश के बाहर से अपने गैंग चला रहे गिरोह के गुर्गे वसूली, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग, सुपारी किलिंग और रंगदारी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीते एक महीने में एक के बाद एक हुईं तीन बड़ी घटनाएं पुलिस की कार्यशैली और मुखबिर तंत्र पर सवाल खड़े कर रही हैं।

मशहूर हरियाणवी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के 20 दिन बाद उसके करीबी रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या और फिर अब मशहूर यूट्यूबर व राहुल के दोस्त एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये तीन मामले एक महीने के अंदर ही हुए हैं। इन घटनाओं की एक-दूसरे से जुड़े हुए गैंगस्टरों ने ही जिम्मेदारी ली है। राहुल कर दी गई थी। बताया गया था कि दीपक नांदल ने ही रोहित को फोन कर गुरुग्राम बुलाया था। उसके बाद वारदात की गई, जिस तरह रविवार सुबह एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, इसका मकसद गैंगस्टर द्वारा इलाक

की गिरफ्त दूर हैं। गुरुग्राम पुलिस को चुनौती देती हुई अब ये तीसरी घटना रविवार सुबह हुई जिसमें पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। राहुल फाजिलपुरिया पर 14 जुलाई की रात फायरिंग की गई थी। कार सवार हमलावरों ने उनका पीछा किया था और एस्पीआर रोड पर उनकी थार गाड़ी रुकवाकर गोलीबारी की थी। इस हमले में राहुल फाजिलपुरिया बाल-बाल बच गए थे। इस हमले के बाद गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि अगर वह दीपक नांदल के पांच करोड़ नहीं देगा तो उसके करीबियों की हत्या की जाएगी।

इस धमकी की 20 दिन बाद ही राहुल के करीबी दिव्ने के नांगलौड़ के रहने वाले रोहित शौकीन की राहुल के घर के पास ही एस्पीआर रोड पर 4 अगस्त की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया था कि दीपक नांदल ने ही रोहित को फोन कर गुरुग्राम बुलाया था। उसके बाद वारदात की गई, जिस तरह रविवार सुबह एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, इसका मकसद गैंगस्टर द्वारा इलाक

में दहशत पैदा करना है।

गैंगस्टर गोल्डिया मारकर हत्या करना और इतनी बड़ी संख्या में फायरिंग करने का डंड अनपनाते रहे हैं। इसकी शुरुआत गैंगस्टर कोशल गिरोह ने की थी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई, फिर उससे जुड़े हुए गिरोह के लोगों ने इसी तरह से कई हत्याएं कीं। घटना के बाद गैंगस्टर का नाम जुड़ने ही एसटीएफ की टीमें भी सतर्क होग गई हैं। राहुल फाजिलपुरिया पर हमला, रोहित शौकीन की हत्या के बाद अब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के मामले में भी एसटीएफ की टीम अपनी तरफ से जांच में जुट गई हैं।

एसटीएफ के सूत्रों का कहना है कि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं या कोई गैंगस्टर इस तरह से घटना की जिम्मेदारी लेता है तो एसटीएफ खुद ही संज्ञान लेकर उस पर काम शुरू कर देती है। एसटीएफ की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर टीमें जांच कर रही हैं। पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप कुमार ने कहा कि सभी मामलों में पुलिस टीमें तेजी से जांच कर रही हैं। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कोलकाता(एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में इस बार 45 हजार से ज्यादा दुर्गा पंडाल बनाए जा रहे हैं। इनमें से 3100 सिर्फ कोलकाता में लगाए जाएंगे। साल 2026 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बार सीएम ममता बनर्जी हरेक पंडाल को 1.10 लाख रुपए की अनुदान राशि दे रही हैं। इस हिसाब से देखें तो राज्य सरकार करीब 500 करोड़ रुपए दुर्गा पंडालों को मदद दे रही हैं।

बता दें सीएम ममता बनर्जी ने 2018 में पंडालों को अनुदान देना शुरू किया था। तब 28 हजार पंडाल थे और हरेक को 10 हजार रुपए दिए जाते थे। अब पंडाल 60 फीसदी बढ़ गए हैं और अनुदान 11 गुना। पिछले साल 85 हजार रुपए दिए गए थे। इस बार सीधे 25 हजार रुपए बढ़ाए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए सीएम ममता ने अनुदान बढ़ाया है।

विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स विभाग के एचओडी कहते हैं, 10 दिनी शारदीय नवरात्र बंगाल की अर्थव्यवस्था की रौद है। यह छठे से लेकर अठे सेक्टर

राहुल गांधी का समर्थन कर प्रशांत किशोर ने दी चुनाव आयोग को चुनौती

पटना (एजेंसी)। जन सुराज के संस्थापक और पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में आकर चुनाव आयोग (ईसीआई) को चुनौती दी है। यह मामला तब सामने आया जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए मतदाता सूची से संबंधित आरोपों को निराधार बताकर उन्हें अपने दावों का सबूत देने के लिए 7 दिन की मोहलत दी, अन्यथा पूरे देश से माफी मांगने की बात कही। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग को आरोपों का बिंदुवार जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि वह राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह दें। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर कहा कि अगर राहुल गांधी चुनाव आयोग की बात नहीं मानते हैं, तब चुनाव आयोग क्या कर लेगा? पीके ने इस मुद्दे को राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग बनाने के बजाय, सार्वजनिक डोमेन में मौजूद जानकारी के रूप में देखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को खुद ही इन मामलों की जांच करनी चाहिए और जांच के बाद बिंदुवार उत्तर देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से फॉर्म 20, फॉर्म 19 और फॉर्म 6 जैसे डिजिटल डेटा को सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग के प्राइवसी के तर्कों को खारिज कर कहा कि एहसास लोगों को बेवकूफ बनाने जैसा है। पीके ने यह भी स्पष्ट किया कि राहुल गांधी ने मतदाताओं को चोर नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं।



पर भी बारिश जारी रही। बदरीनाथ हाईवे के पगल नाला और भन्सेपुर सहित अन्य हिस्सों पर मलबा और बोल्टर गिरने से सड़क अवरुद्ध रही। जिले में करीब 20 ग्रामीण सड़कें भी बंद पड़ीं, जिन्हें मशीनों से मलबा हटकर सुचारू किया जा रहा है।

बंगाल में लगेंगे 45 हजार दुर्गा पंडाल, सीएम ममता पंडालों को दे रही 500 करोड़



तक को आर्थिक ताकत देती है। सरकारी आंकड़ों है कि पिछले साल इन 10 दिन में 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ था। इस बार यह एक लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि हर चीज के दाम पिछले साल से ज्यादा हैं और पंडाल भी बढ़ गए हैं। पूजा कमेडियों का कहना है कि बीते साल ताल में लेबर, कच्चा माल, लाइटिंग, पूजन सामग्री, सजावट आदि का खर्च 60 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए पंडालों को भी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।

स्कॉपर पूजा पंडाल के आयोजक



संक्षिप्त समाचार

बस-एम्बुलेंस की टक्कर में छह लोगों की मौत, मुख्यमंत्री मरियम ने जताया शोक

लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान ज़िले में एक यात्री बस और एम्बुलेंस की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चार रेस्क्यू कर्मी शामिल हैं। गुरुवार को हादसा तब हुआ जब बस ने एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में सामने से आ रही रेस्क्यू वाली गाड़ी 1122 एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। चार रेस्क्यू कर्मियों को मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए। दो घायलों की हालत गंभीर है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने हादसे पर दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की।

डेल्टा और यूनाइटेड एयरलाइंस पर धोखा देने का केस

न्यूयॉर्क, एजेंसी। इस हफ्ते न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेडएयरलाइंस के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने खिड़की वाली सीट बताकर यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूलें, जबकि कई सीटों के पास खिड़की थी ही नहीं सिर्फ दीवार थी। यह मुकदमे न्यूयॉर्क की एक कानून फर्म ने दर्ज किए हैं और ये सामूहिक मुकदमे हैं, यानी कोई भी यात्री जिसने ऐसी सीट बुक की हो, इस केस का हिस्सा बन सकता है। कानून फर्म ने कहा कि हमें बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इस केस से जुड़ना चाहते हैं। जब लोग खिड़की के लिए पैसे देते हैं, तो उन्हें खिड़की मिलनी भी चाहिए। डेल्टा और यूनाइटेड दोनों एयरलाइंस ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है क्योंकि केस कोर्ट में चल रहा है।

शत्रु वेले अमेरिकी धोखाधड़ी केस की जांच में गिरफ्तार, बाद में मिली जमानत

अक्रा, एजेंसी। घाना के मशहूर सिंगर शत्रु वेले को अमेरिका में चल रहे एक धोखाधड़ी मामले से जुड़े जांच के सिलसिले में हिरास्त में लिया गया। वह मामला उनकी 2019 मॉडल की लज़री कार लेम्बोर्गिनी उरुस से जुड़ा हुआ है। घाना की आर्थिक और संगठित अपराध कार्यालय ने बताया कि शत्रु वेले खुद बुधवार को पूछताछ के लिए पेश हुए थे। यह पूछताछ अमेरिका सरकार की ओर से आए अनुरोध पर हो रही है। उन्हें गुरुवार को जमानत पर छोड़ दिया गया। जांच एक 4 मिलियन डॉलर (करीब 33 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी से जुड़ी है, जो अमेरिका में कुछ घानावासियों द्वारा की गई थी। इस धोखाधड़ी में कमाई गई रकम से खेतीवाई चाँची को पता लगाया जा रहा है। इस केस का मुख्य आरोपी नाना क्रोबेना अनुआह है, जिसे 2023 में अमेरिका की अदालत ने 7 साल की सजा दी थी। उस पर आरोप था कि उसने लेक्सिंग्टन, केंटकी शहर को गैर-लाभकारी संगठनों के नाम पर धोखा देकर पैसे ठग लिए।

फलस्तीनी गुटों ने हथियार सौंपने की प्रक्रिया शुरू की, लेबनानी सेना को सौंपी पहली खेप

बेरूत , एजेंसी। बेरूत के पास एक फलस्तीनी शरणार्थी कैंप में मौजूद कुछ फलस्तीनी गुटों ने गुरुवार को अपने पास रखे हथियार लेबनानी सेना को सौंपने की शुरुआत की। यह कदम उन योजनाओं का हिस्सा है जो तीन महीने पहले घोषित की गई थी, जिसके तहत इन कैंपों से हथियार हटाए जाने हैं। पहले दिन एक छोटी सी शुरुआत हुई, एक पिकअप ट्रक कैैंप से निकला जिसमें बैगों में बंद हथियार रखे थे। कुछ बैगों से मशीन गनों के पिछले हिस्से और रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स झांकेते हुए दिखाई दिए। इस योजना की घोषणा मई में उस समय हुई थी जब फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने लेबनान का दौरा किया था। उन्होंने और लेबनान के राष्ट्रपति जोसफ आउन ने मिलकर कहा था कि हथियारों का नियंत्रण अब लेबनानी सरकार के पास होगा। लेकिन अभी तक सभी फलस्तीनी गुट इस फैसले से सहमत नहीं हैं। हम़ास और उससे जुड़े गुट पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हम़ास की ओर से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि गुरुवार को हथियार सौंपना फतह संगठन का आंतरिक मामला है और इसका फलस्तीनी कैंपों में मौजूद हथियारों से कोई लेना-देना नहीं है।

भारत पर टैरिफ लगाने और चीन को बचाने पर ट्रंप को विशेषज्ञों की चेतावनी

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने पर विशेषज्ञों ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाने और चीन को बचाने से अमेरिका को ही नुकसान हो सकता है। भारत पर टैरिफ लगाने से दोनों देशों के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। भू-राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के खिलाफ इस हमले का भारत-अमेरिका संबंधों पर दूरागीमी और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप की सहयोगी निक्की हेली ने एक लेख में कहा कि चीन को पछाड़ने के अमेरिकी विदेश नीति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को पटरी पर लाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं है। भारत से मूल्यवान स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार की तरह



व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी की तरह। एशिया में चीनी प्रभुत्व के प्रतिकार के रूप में काम करने वाले एकमात्र देश के साथ 25 वर्षों की गति को रोकना एक रणनीतिक आपदा होगी। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका को अपनी महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर ले जाने में मदद करने के लिए आवश्यक है और यह स्वतंत्र विश्व की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण परिस्ंपति है। जबकि ट्रंप प्रशासन विनिर्माण को अमेरिका में वापस लाने के लिए काम कर रहा है। भारत उन उत्पादों के लिए चीन जैसे पैमाने पर विनिर्माण करने की क्षमता के मामले में अकेला है, जिनका उत्पादन यहां शीघ्रता से या

कहा- संबंधों पर पड़ेगा प्रभाव

कुशलता से नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कपड़ा, सस्ते फोन और सौर पैनल। हेली ने कहा कि चीन के विपरीत लोकतांत्रिक भारत का उदय स्वतंत्र विश्व के लिए खतरा नहीं है और इसलिए भारत की शक्ति बढ़ने के साथ ही चीन की महत्वाकांक्षाएं कम होनी होंगी। भू-राजनीतिक विशेषज्ञ फरीद जकारिया ने अमेरिका भारत संबंधों को खराब करने के लिए ट्रंप की आलोचना की। जकारिया ने कहा कि ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए दंडात्मक टैरिफ अमेरिका की सबसे बड़ी विदेश नीति गलती थी। अगर ट्रंप अपना रुख बदल भी देते हैं, तो भी नुकसान हो चुका है। भारत का मानना है कि अमेरिका ने अपना असली रंग दिखा दिया है। वह अविश्वसनीय है और जिसे वह अपना दोस्त कहता है, उसके साथ क्रूरता करने को तैयार है। भारत को लोगों कि उसे अपनी बाजी सुरक्षित रखनी होगी। रूस

के साथ नजदीकी बनाए रखें और चीन के साथ सुलह करें। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने भी भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के ट्रंप के कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिक्स के महान एकीकरणकर्ता हैं। उन्होंने टैरिफ को अमेरिकी विदेश नीति में सबसे मूर्खतापूर्ण रणनीतिक कदम कहा। वरिष्ठ अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने भी भारत पर टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ से वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच मजबूत साझेदारी बनाने के लिए दो दशकों से अधिक समय से किए जा रहे सावधानीपूर्वक कार्य को खतरा है। हमारे बीच गहरे रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंध हैं। चिंताओं का समाधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप पारस्परिक सम्मान के साथ किया जाना चाहिए।

मनी लॉड्रिंग मामले में घिरे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति पुलिस ने लगाए 50 लाख डॉलर के लेनदेन के आरोप

ब्रासीलिया, एजेंसी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर् बोलसोनारो मनी लॉड्रिंग मामले में घिर गए हैं। पुलिस ने उन पर मार्च 2023 और फरवरी 2024 के बीच 50 लाख डॉलर का लेनदेन करने के आरोप लगाए हैं। वहीं बोलसोनारो ने कहा कि राष्ट्रपति लुईस इनसियायो लुला दा सिल्वा की सरकार उन्हें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। बोलसानारो एक जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2022 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रहे। उन पर तख्तापलट की साजिश करने का भी आरोप है। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों का एक पैनल सजा सुनाएगा। वे दो से 12 सितंबर के बीच अपना फैसला सुनाएंगे। अगर अर्दोनी जनरल उन पर न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाने का निर्णय लेते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति को एक और मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। बोलसनारो पर आरोप है कि उनको 30 मिलियन से अधिक ब्राजीलियन रीसिस (5 मिलियन डॉलर) प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश बिना किसी स्पष्ट औचित्य के थे तथा उस अवधि के दौरान लगभग इतनी ही राशि के डेबिट भी प्राप्त हुए। दस्तावेजों के मुताबिक लगभग दो करोड़ रियाल (3.48 मिलियन डॉलर) कथित तौर पर पीआईएक्स नामक 12 लाख से अधिक लेनदेन से आए। बोल्लोनारो ने इस दौरान निवेश पर भी इतनी ही राशि खर्च की। दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि पूर्व राष्ट्रपति ने वायर ट्रांसफर, जमा पंचियों के भुगतान,



निकासी और विनिमय कार्यों पर भी पैसा खर्च किया। ब्राजील पुलिस ने कहा है कि बोलसोनारो और उनके बेटे एडुआर्डो ने वित्तीय संसाधनों के स्रोत और गंतव्य को छिपाने के लिए कई पैतरेबाजी की। इसका उद्देश्य विदेश में रहने वाले सांसद (एडुआर्डो बोलसोनारो) की अवैध प्रकृति की गतिविधियों को वित्तपोषित करना और उनका समर्थन करना था। पुलिस जांच यह भी खुलासा हुआ कि बोलसोनारो ने पिछले साल अर्जेंटीना में राजनीतिक शरण लेने पर विचार किया था और एह्तियाती उपायों के बावजूद हाल के हफ्तों में उन्होंने सहयोगियों के साथ सवाद जारी रखा, जिसके कारण अब उन्हें नजरबंद होना पड़ रहा है। मामले की देखरेख कर रहे न्यायमूर्ति एलेक्जेंडर डी मोरेस ने बुधवार देर रात बोलसोनारो के वकीलों से कहा कि उनके पास यह बताने के लिए 48 घंटे का समय है कि पूर्व राष्ट्रपति अपने घर में नजरबंदी के आदेश के लिए निर्धारित उपायों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलसोनारो के वकीलों ने उस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने जब्त किया पासपोर्ट

ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी, 2024 को बोलसोनारो का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। न्यायाधीश डी मोरेस ने सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति के भाग जाने का खतरा माना जा रहा है। वहीं बोलसोनारो ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को दिए 33 पन्नों के एक दस्तावेज में दावा किया है कि ब्राजील में उनका राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है। दोनों ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। माइली के प्रवक्ता मैनुअल एडोनी ने कहा कि अर्जेंटीना सरकार को अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है।

किया। वकीलों ने कहा कि किसी भी एह्तियाती उपाय का कभी भी उल्लंघन नहीं किया गया था। साथ ही वे संघीय पुलिस द्वारा उन पर औपचारिक रूप से न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाने के निर्णय से आश्चर्यचकित हैं। बोलसोनारो के एक वकील ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने कभी भी अर्जेंटीना में राजनीतिक शरण लेने पर गंभीरता से विचार नहीं किया। पाउलो कुन्हा ब्यूनो ने बताया कि बोलसोनारो को उनके खिलाफ जांच के दौरान हर तरह के सुझाव मिले। किसी ने उन्हें फरवरी 2024 में शरण का अनुरोध भेजा था। वह जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

भारतीय की लापरवाही से हुई दुर्घटना, अमेरिका ने सभी विदेशी ट्रक ड्राइवरों का वीजा रोका

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सरकार ने विदेशी ट्रक ड्राइवरों को वीजा देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गुरुवार को इसका एलान कर दिया। दरअसल अमेरिका में एक भारतीय ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद अमेरिका में विदेशी ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ माहौल बन गया है और इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है। मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों को जारी होने वाले वीजा पर रोक लगाई जाती है। अमेरिका की सड़कों पर विदेशी ट्रक ड्राइवरों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये ट्रक और ट्रैनर चालक अमेरिकी लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं

और साथ ही अमेरिकी ट्रक चालकों की आजीविका में भी संंध लगा रहे हैं। **भारतीय ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा**: दरअसल प्लोरिडा के राजमार्ग पर एक भारतीय ट्रक ड्राइवर ने गलत तरीके से यू-टर्न लिया, जिससे एक कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। आरोपी ट्रक ड्राइवर की पहचान हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो मेक्सिको के जॉरिए अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ था। संघीय अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ट्रक ड्राइवर अंग्रेजी परीक्षण में भी असफल रहा। अमेरिका में इस मामले की कार्पी चर्चा हो रही है क्योंकि यह घटना फ्लोरिडा में हुई, जो सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ है। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी का अवैध अप्रवासियों पर रुख सख्त रहा है।

पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा को बड़ी राहत, शाही परिवार को बदनाम करने के मामले में किए गए बरी

बैकॉक, एजेंसी। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को शाही मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। पूर्व पीएम शिनावात्रा ने कहा कि शुक्रवार को एक अदालत ने उन्हें मानहानि के मामले में बरी कर दिया। उनके वकील ने भी फैसले की पुष्टि की। हालांकि बैकॉक आपराधिक न्यायालय ने कोई बयान जारी नहीं किया है। पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा पर थाईलैंड की राजशाही को बदनाम करने के आरोप में औपचारिक रूप से केस दर्ज कराया गया था। जो देश की राजनीति को अस्थिर करने वाले कई अदालती मामलों में से एक है। थाकसिन पर मूल रूप से 2016 में लेसे मैजेस्टे कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने एक साल पहले दक्षिण कोरिया के सियोल में पत्रकारों से बात करते हुए टिप्पणी की थी। हालांकि थाकसिन ने आरोपों से इनकार किया था और खुद का बचाव करते हुए एक बयान जारी किया था। थाईलैंड में राजतंत्र को बदनाम करने के लिए बनाए गए कानून के तहत किसी भी शास्त्र को तीन से 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस कानून को



लेसे मैजेस्टे के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया के इस तरह के सबसे कठोर कानूनों में से एक है। इसी कानून के उल्लंघन के आरोप में थाकसिन पर केस दर्ज कराया गया था। 18 साल पहले थाईलैंड की राजनीति से बेखुश किए पूर्व प्रधानमंत्री थकसिन शिनावात्रा आज भी देश में एक प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती है। दरअसल थकसिन शिनावात्रा को थाईलैंड का सबसे सफल चुना हुआ नेता माना जाता है। तख्तापलट के जरिए सत्ता से बाहर किए जाने के बाद उनपर प्रतिबंध भी लगाया गया था। वहीं थाकसिन ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था।

साल 2008 में लगा था भ्रष्टाचार का आरोप

दो बार थाईलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके थाकसिन एक अरबपति नेता हैं, जो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। थाकसिन ने साल 2001 से 2006 तक थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। हालांकि, साल 2006 के सैन्य तख्तापलट में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। साल 2008 में थाकसिन पर भ्रष्टाचार और सत्ता के पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद वह थाईलैंड छोड़कर भाग गए थे और करीब 15 साल के आत्म-निर्वासन बाद, पिछले साल अगस्त में वापस अपने देश आ गए, जिसके बाद उन्हें उनके आरोपों के लिए सजा सुनाई गई। उन्होंने अपनी सजा का पूरा समय पुलिस के अस्पताल में बिताया, जिसके बाद विरोधियों ने उन पर विशेषाधिकार होने का भी आरोप लगाया है। थाकसिन को अगस्त 2023 में भ्रष्टाचार के आरोप में आठ साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही थाईलैंड के राजा महा वजिरालोंगकोर्न ने शाही माफ़ी दे दी, जिसके बाद उनकी सजा आठ साल से घटाकर एक साल कर दी गई थी।

एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन

94 की उम्र में ली अंतिम सांस

लंदन, एजेंसी। प्रमुख एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का बृहस्पतिवार शाम (स्थानीय समयानुसार) लंदन में निधन हो गया। पारिवारिक स्रोतों के अनुसार, वह 94 साल के थे। हाल ही में बीमार पड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में अंतिम सांस ली। ब्रिटेन स्थित कैपारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक पॉल का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। 1960 के दशक में वह अपनी छोटी बेटी अंबिका के कैरियर के इलाज के लिए ब्रिटेन गए थे। लेकिन बेटी की चार साल की उम्र में मृत्यु हो गई, जिसके बाद पॉल ने एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में अंबिका पॉल फाउंडेशन की स्थापना की। इस संस्था ने शिक्षा और स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से दुनिया भर के बच्चों और युवाओं के कल्याण के लिए लाखों डॉलर का दान किया।



2015 में बेटा और 2022 में पत्नी को खोया

पिछले महीने लंदन के अंबिका पॉल चिल्ड्रन्स जू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लॉर्ड पॉल ने कहा था कि यह वह जगह है,

जहां अंबिका सबसे ज्यादा खुश रहती थीं। लॉर्ड पॉल ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे। उन्होंने 2015 में अपने बेटे अंगद पॉल को खोया और 2022 में पत्नी अरुणा को। उनकी याद में वे लगातार प्रोपेकारी काम करते रहते थे।

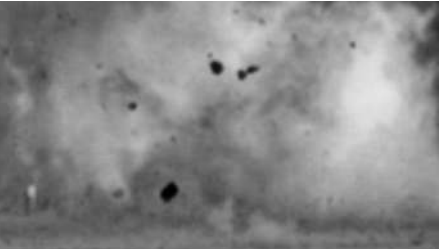
पत्नी की याद में लेडी अरुणा स्वराज पॉल हॉल का किया था उद्घाटन

फरवरी 2023 में, लंदन के ऐतिहासिक इंडियन जिमखाना क्लब में लेडी अरुणा स्वराज पॉल हॉल का उद्घाटन करते हुए लॉर्ड पॉल ने कहा, यह हॉल मेरी अद्भुत पत्नी को श्रद्धांजलि है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। हमारे 65 साल के वैवाहिक जीवन में हमने कभी झगड़ा नहीं किया।

संडे टाइम्स रिव लिस्ट में नियमित शामिल होते रहे हैं लॉर्ड पॉल

लॉर्ड पॉल संडे टाइम्स रिव लिस्ट में नियमित रूप से शामिल होते रहे हैं। इस साल उनकी संपत्ति लगभग 2 बिलियन पाउंड आंकी गई और उन्हें 81वें स्थान पर रखा गया। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी कैपारो समूह से आता है, जो स्टील और इंजीनियरिंग का बड़ा बिजनेस है। कैपारो समूह का मुख्यालय लंदन में है और यह 40 से ज्यादा जगहों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, जिसका संचालन यूक्रे, उत्तरी अमेरिका, भारत और मध्य पूर्व में स्थित है। उनके बेटे आकाश पॉल कैपारो इंडिया के अध्यक्ष और कैपारो समूह के निदेशक हैं।

कराची में गोदाम में धमाके से दो की मौत, 33 घायल पटाखों के कच्चे माल से हुआ बड़ा हादसा



कराची, एजेंसी। पाकिस्तान के कराची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां कराची के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास गुरुवार को एक गोदाम में जोरदार धमाका हो गया। हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है और 33 लोग घायल हुए हैं। मामले में पाकिस्तान की आधिकारिक बहु-खतरा आपातकालीन सेवा रेस्क्यू 1122 के मुताबिक, धमाका एक तीन मंजिला इमारत के बेसमेंट में हुआ जहां पटाखे बनाने का कच्चा माल रखा गया था। ऊपर की मंजिलों पर परिवार रहते थे। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने और फिर ज्वलनशील पदार्थ

की वजह से धमाका होने की बात सामने आई है। बता दें कि हादसे में 20 घायल जिन्ना पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में भर्ती हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक है। 14 घायल सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हैं। बाद में घटनास्थल से 16 साल के एक लड़के की लाश मिली और एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

सीटीडी ने बताया विस्फोटक

वहीं इस धमाका को लेकर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) के अधिकारी राजा उमर खताब ने बताया कि वहां केवल पटाखों का नहीं बल्कि भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। उन्होंने कहा कि इस इलाके से पहले भी दो टन विस्फोटक बरामद हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार, सिंध में पटाखों की कौड़ी वैध फैक्ट्री में रही है और यह गोदाम अवैध रूप से रिहायशी इलाके में चल रहा था। धमाके से इमारत को भारी नुकसान हुआ, आसपास की गाड़ियों पर कंक्रीट के टुकड़े गिर गए और आसपास की खिड़कियां भी टूट गईं। आग बुझाने के लिए 12 फायर ब्रिगड की गाड़ियां लगाई गईं। वहीं मामले में मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने सभी घायलों को तुरंत इलाज दिलाने के निर्देश दिए और घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

अफ्रीकी देश गिनी में

भूस्खलन से 11 लोगों की मौत, 10 घायल

कोनाक्री , एजेंसी। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनाक्री से 50 किलोमीटर दूर कोयाह प्रांत में भारी बारिश के कारण भूस्खलन में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार भूस्खलन बुधवार रात कोयाह प्रांत के ग्रामीण क्षेत्र मानेह में हुआ। स्थानीय निवासी कोने पेपे ने बताया, “कल शाम करीब सात बजे बारिश हो रही थी। मैंने देखा कि अचानक पहाड़ टूटकर तलहटी में बने घरों पर गिर गया। इसके मलबे में घर दफन हो गए। कोई भी जीवित नहीं बचा।” खोज और बचाव अभियान बृहस्पतिवार देर रात तक जारी रहा। शहरी नियोजन एवं आवास मंत्री मोरी कोंडे ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा, “बारिश के कारण पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया और इमारतों पर गिर गया।”

बड़े बदलाव को लेकर 3-4 सितंबर को बैठक कर सकती हैं जीएसटी परिषद, चार की जगह सिर्फदो स्लैब पर बन सकती हैं सहमति



नई दिल्ली।

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3-4 सितंबर को हो सकती है। बैठक में मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत की बरकरार रखने के प्रस्ताव पर फैसला होगा। रिपोर्ट के अनुसार, परिषद की बैठक केंद्र द्वारा जीएसटी कराधान व्यवस्था के ढांचे को वर्तमान चार स्लैब से

दो स्लैब में बदलने के बड़े पैमाने पर प्रयास के बीच हो रही है। छह सदस्यीय जीओएम का नेतृत्व करने वाले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, हमारे द्वारा दो स्लैब वाली जीएसटी स्ट्रक्चर की सिफारिश की है और अपनी सिफारिशें जीएसटी परिषद को सौंप दी हैं।

जीओएम ने सहमति व्यक्त की कि नई व्यवस्था के तहत मौजूदा

12 और 28 प्रतिशत स्लैब को समाप्त करने की बात कही है। इसका उद्देश्य एक सरल और अधिक पारदर्शी जीएसटी व्यवस्था की ओर बढ़ना है। देश में वर्तमान में चार स्लैब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाला जीएसटी सिस्टम लागू है। साथ ही सिन और लक्जरी गुड्स पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जाता है।

नए स्ट्रक्चर के तहत, मैरिट वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि अधिकांश अन्य वस्तुएं (स्टैंडर्ड) 18 प्रतिशत के स्टैंडर्ड रेट के दायरे में आएंगी। कुछ तथाकथित सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत का उच्च कर लागू रहेगा। उदाहरणों में शराब, तंबाकू, ड्रग्स, जुआ, शीतल पेय, फास्ट फूड, कॉफी,

चीनी और पौनोग्रामी भी शामिल हैं। सिन टैक्स एक विशेष कर है, जो सरकार द्वारा इस प्रकार की वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को इनके उपयोग से हतोत्साहित करना और इनसे होने वाले नुकसान को कम करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले दो दिवसीय मंत्रिसमूह की बैठक को संबोधित कर कहा था कि एक सरलीकृत प्रणाली से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को लाभ होगा, साथ ही जीएसटी को अधिक पारदर्शी और विकासोन्मुखी भी बनाया जा सकेगा। बदलावों के तहत, वर्तमान में 12 प्रतिशत कर श्रेणी में आने वाली लगभग सभी वस्तुएं 5 प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगी।

नई जीएसटी दरों पर असमंजस: ऑटोमोबाइल कंपनियों को उपभोक्ता की प्रतिक्रिया का इंतजार



- मंत्रिसमूह के स्लैब के प्रस्ताव के बीच वाहन उद्योग में आशंका और उम्मीद का माहौल

नई दिल्ली । सरकार द्वारा प्रस्तावित नई जीएसटी व्यवस्था के तहत 12 और 28 फीसदी टैक्स स्लैब को हटाकर केवल 5 और 18 फीसदी दरें लागू करने की संभावना पर वाहन उद्योग में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई कंपनियों को डर है कि जब तक जीएसटी परिषद इस पर अंतिम फैसला नहीं लेती, तब तक ग्राहक वाहन खरीदने में देरी कर सकते हैं, जिससे बिक्री प्रभावित हो सकती है।

मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भागवत का कहना है कि वर्तमान में बड़ी कारों पर कुल कर भार 40-45 फीसदी तक पहुंचता है। यदि नई व्यवस्था में उपकर हटा दिया जाता है और

केवल 18 फीसदी टैक्स लागू होता है, तो यह बदलाव बड़ी राहत ला सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता अभी भी वाहन खरीद रहे हैं, इसलिए फिलहाल बाजार में कोई ठहराव नहीं दिख रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बड़ी कारों पर उपकर हटता है, तो छोटी कारों की कीमतीय प्रतियस्पर्धा घट सकती है, जिससे उनकी मांग प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद यह बदलाव वाहन उद्योग की कुल बिक्री को बढ़ा सकता है। दोपहिया वाहन क्षेत्र में भी प्रतिक्रिया बंटी हुई है।

बजाज ऑटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी में राहत की घोषणा के बावजूद ग्राहकों की खरीद में देरी का कोई संकेत नहीं मिला है। उद्योग जगत को अब जीएसटी परिषद के अंतिम फैसले का इंतजार है, जो बाजार की दिशा तय करेगा।

1 सितंबर से बजाज आलियांज पॉलिसीधारकों को अस्पतालों में कैशलेस सुविधा नहीं: एचपीआई



पुराने टैरिफ, पेमेंट कटौती और मेडिकल इन्फ्लेशन को लेकर असंतोष; अस्पतालों ने रिएम्बर्समेंट विकल्प रखा

नई दिल्ली ।

एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स-इंडिया (एचपीआई) ने घोषणा की है कि उसके सदस्य अस्पतालों में 1 सितंबर से बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस के पॉलिसीधारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं देंगे। संगठन के तहत 15,200 से अधिक निजी अस्पताल आते हैं, जिनमें मैक्स हेल्थकेयर और मेदांता जैसे प्रमुख नाम भी शामिल हैं। एचपीआई का आरोप है कि बजाज आलियांज अस्पतालों को पुराने टैरिफ पर भुगतान कर रहा है, जबकि मेडिकल खर्चों में सालाना 7-8 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा कंपनी पर प्री-ऑथ

और डिस्चार्ज अप्रुवल में देरी और पेमेंट में मनमानी कटौती के भी आरोप लगाए गए हैं। संगठन का कहना है कि इस स्थिति में अस्पतालों के लिए गुणवत्तापूर्ण इलाज जारी रखना कठिन हो गया है। हालांकि एचपीआई ने स्पष्ट किया कि इलाज पूरी तरह बंद नहीं होगा। मरीजों को सेल्फ-पे आधार पर इलाज मिलेगा और वे बाद में कंपनी से रिएम्बर्समेंट क्लेम कर सकेंगे। संगठन ने इसी तरह की शिकायत के चलते केयर हेल्थ इश्योरेंस को भी नोटिस भेजा है और चेतावनी दी है कि 31 अगस्त तक जवाब नहीं मिलने पर उनकी भी कैशलेस सुविधा बंद की जा सकती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, बजाज आलियांज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कंपनी पॉलिसीधारकों को बेहतर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है और संवाद के जरिए समाधान निकालने की उम्मीद है।

रूस से सस्ते तेल का लाभ निजी कंपनियों तक सीमित

- रिलायंस और नायरा ने उठाया सबसे ज्यादा मुनाफा, सरकारी कंपनियां पीछे रहीं

नई दिल्ली।

रूस से सस्ते कच्चे तेल का आयात भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद रहा, लेकिन इसका लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिला। निजी क्षेत्र की दो बड़ी कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी ने इस अवसर का सबसे अधिक फायदा उठाया। उद्योग सूत्रों और रिफाइनमेंट डेटा के अनुसार देश की सात प्रमुख रिफाइनिंग कंपनियों ने रोजाना करीब 18 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा, जिसमें से करीब 8.81 लाख बैरल प्रतिदिन अकेले इन दो निजी कंपनियों के हिस्से में आया। नायरा एनर्जी को रूस की सरकारी कंपनी रोसेनेफ्ट नियंत्रित करती है। सरकारी रिफाइनरियों को

घरेलू बाजार में तय कीमतों पर ईंधन बेचने की बाध्यता के कारण अपेक्षाकृत कम मुनाफा हुआ। वहीं, निजी कंपनियों ने सस्ते रूसी तेल को रिफाइन कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा। अमेरिकी वित्त मंत्री के अनुसार भारतीय कंपनियों को ऐसे सौदों से अब तक करीब 16 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ है। उन्होंने इसे जंग के समय मुनाफाखोरी करार दिया। फिनलैंड की एक संस्था की रिपोर्ट बताती है कि जी7 प्लस देशों ने भारत और तुर्की की 6 रिफाइनरियों से 21 अरब डॉलर के ईंधन उत्पाद खरीदे, जिनमें से लगभग 9 अरब डॉलर के उत्पाद रूसी कच्चे तेल से बने थे। रिलायंस की जानमगर रिफाइनरी ने अकेले ही 12 अरब यूरो का ईंधन निर्यात किया, जिसमें

भुगतान 1 अक्टूबर को किया जाएगा। डिविडेंड का लाभ पाने के लिए निवेशकों को रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर अपने डीमैट अकाउंट में रखने होंगे। पिछले कुछ वर्षों में आईआरसीओएन ने नियमित रूप से अच्छा डिविडेंड दिया है। फरवरी 2025 में कंपनी ने 1.65 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। वर्ष 2024 में

कंपनी ने दो बार 1.80 और 1.30 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया। वहीं, 2023 में 3 रुपए और 2022 में 1.35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड निवेशकों को मिला था।



अमेरिकी सरकार ने इटेल में 10 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी

- चिप उद्योग को मिलेगी मजबूती

वॉशिंगटन । अमेरिकी

सरकार ने चिपमेकर कंपनी इटेल में करीब 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इस डील की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटेल के सीईओ ने की। पिछली बाइडेन सरकार ने इटेल को आर्थिक मदद देने का एलान किया था, लेकिन ट्रंप ने इस सहायता के बदले कंपनी में हिस्सेदारी लेने की मांग की थी। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद अब सरकार को इटेल के सामान्य स्टॉक के 43.3 करोड़ शेयर मिले हैं, जो कंपनी का 9.9 प्रतिशत है। इस हिस्सेदारी की कीमत करीब 8.9 अरब डॉलर है, जिसमें से 5.7 अरब डॉलर चिप्स और विज्ञान कानून के तहत अनुदान के रूप में दिया जाएगा। बाकी 3.2 अरब डॉलर सिक्वोर एन्क्लेव कार्यक्रम के तहत कंपनी को मिलेंगे। इससे पहले ही इटेल को 2.2 अरब डॉलर के अनुदान मिल चुके हैं, जिससे कुल राशि 11.1 अरब डॉलर हो जाती है। इटेल में सरकार का निवेश निष्क्रिय होगा, यानी बोर्ड या कंपनी के संचालन में सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि यह समझौता अमेरिका के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नेतृत्व को मजबूत करेगा। इटेल ने एक समय सिलिकॉन वैली में अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन एशियाई कंपनियों टीएसएमसी और सैमसंग के आने से उसकी स्थिति कमजोर हुई थी। चिप्स और विज्ञान कानून का उद्देश्य अमेरिकी सेमीकंडक्टर उद्योग को पुनर्जीवित करना है।



बीते सप्ताह शेयर बाजार में मिला-जुला रुख रहा

- सेंसेक्स 693 अंक गिरकर 81,306.85

अंक पर बंद

- निफ्टी 213 अंक गिरकर 24,870.50

अंक पर बंद

मुंबई ।

शेयर बाजार में बीते सप्ताह मिला-जुला रुख देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में बाजार में जबर्दस्त तेजी रही, जिसका श्रेय जीएसटी व्यवस्था में संभावित सुधारों और प्रमुख कंपनियों में निवेश बढ़ने को दिया जा सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत में आईटी और बैंकिंग शेयरों में गिरावट के चलते बाजार फिसल गया। यह सप्ताह निवेशकों के लिए भावनात्मक रूप से उतार-चढ़ाव से भरा रहा। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 1,021 अंक की भारी बढ़त के साथ 81,619.59 पर खुला और 676 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने 322 अंकों की छलांग लगाई और 24,876.95 पर बंद हुआ। मंगलवार को भी तेजी बरकरार रही। बाजार ने जीएसटी सुधारों की योजनाओं को सकारात्मक संकेत के रूप में लिया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में मजबूती आई। बुधवार को एशियाई बाजारों के कमजोर संकेतों का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा। हालांकि शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन दिन के



अंत में मामूली तेजी के साथ बाजार बंद हुआ। गुरुवार को रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी से बाजार ने मजबूती दिखाई। सेंसेक्स 82,000 के पार बंद हुआ। आर्टी और बैंक शेयरों की गिरावट की वजह से लगभग एक सप्ताह की तेजी के बाद शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के प्रमुख

सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 262.05 अंक गिरकर 81,738.66 पर खुला और 693.86 अंक गिरकर 81,306.85 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 81.55 अंक गिरकर 25,002.20 पर खुला और 213.25 अंक गिरकर 24,870.50 अंक पर बंद हुआ।

कोट्टि में अदाणी लॉजिस्टिक्स पार्क के शिलान्यास की घोषणा, 70 एकड़ में फैली परियोजना

कोच्चि।

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने कलामासेरी औद्योगिक क्षेत्र में अदाणी लॉजिस्टिक्स पार्क के शिलान्यास की घोषणा की, इसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया। 70 एकड़ में फैली परियोजना 600 करोड़ से अधिक के निवेश वाले केरल में निवेश कार्यक्रम का हिस्सा है। अदाणी लॉजिस्टिक्स पार्क में सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के मध्य नजर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन और डिजिटल इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।

कंपनी के अनुसार, पार्क से 1,500 से अधिक नौकरियों के सृजन की उम्मीद है, जिससे स्थानीय रोजगार, कौशल और आर्थिक

विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही स्टाईड चैन इकोसिस्टम में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए विकास के अवसर पैदा होने हैं। एपीएसईजेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा, कलामासेरी लॉजिस्टिक्स पार्क, एपीएसईजेड के बंदरगाह-केन्द्रित उद्यम से फुल्टी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में हमारे सबसे बड़े प्रयासों में से एक के रूप में, यह पार्क दक्षिण भारत में हमारी लॉजिस्टिक्स उपस्थिति को बेहतर करने, स्थानीय विनिर्माण और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के काम आ जाएगा। उन्होंने कहा, हम वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा दे। यह ऐतिहासिक परियोजना केरल

को एक लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक महाशक्ति में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पार्क कोच्ची में स्थित है, जो कि औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स विकास के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा शहर है। पार्क 70 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है और इसे परिवहन लागत को कम करने, समय पर संचालन को सक्षम बनाने और ई-कॉमर्स, एफएमसीजी,एफएमसीडी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव और खुदरा सहित प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मौके पर केरल के उद्योग मंत्री पी.राजीव ने कहा, कलामासेरी लॉजिस्टिक्स पार्क, एपीएसईजेड के स्मार्ट, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण को दिखाता है, जो व्यापार को बढ़ावा देता है, समुदायों को सशक्त बनाता है और बाजारों को जोड़ता है।

म्यूचुअल फंड उद्योग परिचालन जोखिमों और फर्जीवाड़े से रहे सतर्क- सेबी प्रमुख

एएमसी को त्वरित कार्रवाई और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी मुंबई ।

भारतीय बाजार नियामक सेबी के एक वे रिष्ठ अधिकारी ने म्यूचुअल फंड उद्योग को आगाह किया कि उन्हें केवल बाजार जोखिमों तक सीमित न रहकर परिचालन जोखिमों को भी गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने कहा कि फर्जी निवेशकों द्वारा जालसाजी के मामलों में कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेजों का सहारा लेकर असली निवेशकों की फंड यूनिट्स या राशि निकाल सकता है, जिससे निवेशकों का विश्वास गहराई से प्रभावित होता है। सेबी प्रमुख ने म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में कहा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को ऐसे धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और अपराध के बदलते तरीकों पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि धोखाधड़ी के मामलों की जानकारी सभी एएमसी और रजिस्ट्रार एजेंटों के साथ साझा की जाए ताकि भविष्य में दोहराव से बचा जा सके। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने भी म्यूचुअल फंड उद्योग से जिम्मेदाराना और नैतिक वृद्धि पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतियस्पर्धा और नवाचार के दबाव में उद्योग को अत्यधिक लाभ की बजाय निवेशकों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित हो सके।

तमिलनाडु में जूते-चप्पलों की फैक्ट्री लगाएगा कोरियाई ह्यासंग ग्रुप

चेन्नई । क्षिण कोरिया की प्रमुख कंपनी ह्यासंग फुटवियर ग्रुप मिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में 1,720 करोड़ का निवेश कर गैर-चमड़े के जूते-चप्पलों की फैक्ट्री लगाएगी। यह भारत में कंपनी की पहली यूनिट होगी। इस परियोजना से लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरवी राजा ने बताया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की और निवेश को लेकर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि यह राज्य में फुटवियर क्षेत्र की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली परियोजनाओं में से एक होगी। राज्य सरकार की उद्योग-प्रोत्साहन नीति के तहत यह निवेश तमिलनाडु को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अन्य निवेश समझौतों से भी जल्द नई नौकरियों के अवसर सामने आएंगे।

टिकटाक की भारत में वापसी की अटकलें तेज, वेबसाइट हुई एक्टिव

- कहीं वेबसाइट की उपलब्धता, कहीं भारत-चीन रिश्तों में सुधार की उम्मीदें

जम्मू । टिकटॉक जो 2020 में भारत में बैन हुआ था, उसकी वेबसाइट हाल ही में कुछ उपयोगकर्ताओं के मोबाइल और लैपटॉप पर एक्टिव दिख रही है। हालांकि ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, जिससे साफ नहीं हो पा रहा कि टिकटॉक पूरी तरह से भारत में वापस आ रहा है या नहीं। यह संकेत टेस्टिंग या सीमित रोलआउट के हो सकते हैं। भारत और चीन के बीच रिश्तों में हाल ही में सुधार के चलते टिकटाक की वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, भारत सरकार ने अभी तक टिकटाक की वापसी के लिए कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है। कंपनी की तरफ से भी कोई घोषणा नहीं आई है। फिलहाल टिकटाक भारत में आधिकारिक रूप से बैन ही है और बिना अनुमति काम नहीं कर सकता।

बैंक घोटाले में हिरेन भानु और पत्नी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी

- एस्प्लेनेड कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया

मुंबई । मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु को 122 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। कोर्ट ने पुलिस को दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए क्योंकि वे विदेश फरार हो चुके हैं। कोर्ट ने मामले में शामिल पांच आरोपियों की 167.85 करोड़ रुपए कीमत वाली 21 संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति भी दी है। इस घोटाले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (इंडोअब्ज्यू) कर रही है। अब तक बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हिरेश मेहता, पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन सहित आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई पुलिस अब इंटरपोल की मदद से हिरेन और उनकी पत्नी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया लगभग एक महीने में पूरी हो सकती है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद दोनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तलाश जाएगा। घोटाले के खुलासे के बाद हिरेन भानु फरार हो गए थे। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए इस पूरे घोटाले की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी हितेश मेहता पर डाली है। हिरेन ने बताया कि फरवरी में आरबीआई के अधिकारियों की पहली जांच के दौरान मेहता ने अपने अपराध को स्वीकार किया था।





बॉस हों पार्ट टाइमर तो ऐसे करें डील

वह पावर का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। बॉस का पद जिम्मेदारी भरा पद होता है और कंपनी बॉस पर भी नजर रखती है। याद रखें कि इसके लिए कंपनी हमेशा ही अपने स्तर पर सही व्यक्ति का चुनाव करती है। ऐसे में यह है कि टीम भी सही मानसिकता के साथ बॉस को सहयोग दे और अपना काम करे। वह कॉरपोरेट जगत के वैल्यू को समझे।

कम्प्यूनिकेशन का होता है अहम रोल

जहां बॉस पार्ट टाइम काम करते हैं और उनके साथ काम करने वाले बाकी लोग फुल टाइम

जॉब करते हैं, वहां पर कम्प्यूनिकेशन का रोल अहम हो जाता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसी स्थिति में टीम को बॉस के साथ कम्प्यूनिकेशन लेवल हाई रखना पड़ता है। एक बार कम्प्यूनिकेशन करने का स्टाइल फिक्स हो जाता है, तो बाद में चीजों को बदल पाना आसान नहीं होता है। जब कम्प्यूनिकेशन सही रहेगा तो प्रॉब्लम का निपटारा भी पलक झपकते ही हो जाएगा। ऐसे में पार्ट टाइमर बॉस के संग भी टीम बेहतर रिजल्ट दे सकती है।

फैसला लेने की कला सीखें

आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जहां फुल

टाइमर बॉस नहीं हैं, तो जरूरी है कि टीम का हर एक सदस्य खुद पर भरोसा दिखाए और फैसला लेने की कला सीखें। याद रखें कि जब बॉस फुल टाइमर नहीं होते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत फैसला लेने में ही होती है। वर्कप्लेस पर कई बार आपको पलक झपकते ही बड़े फैसले लेने होते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा यह होता है कि आप आज के कॉम्पिटिशन भरे माहौल में टीम में तेजी कैसे लाएं। जॉब एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे निपटने के लिए कंपनियों को चाहिए कि वह फैसला लेने के अधिकार को बांट दे। इससे जहां टीम के सदस्यों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वहीं समय के भीतर फैसला लेने से काम में तेजी भी आती है।

जॉब के दौरान कई परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी पार्ट टाइम बॉस को नियुक्त कर दे। ऐसी स्थिति में टीम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बॉस के साथ तालमेल बैठाकर उन्हें फैसले लेने होते हैं...

जब आपके ऑफिस में पार्ट टाइम काम करने वाले बॉस हों और आप फुल टाइमर एम्प्लॉई हों, तो स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो जाती है। ऐसे में पूरी टीम को बॉस के साथ बराबर टच में रहना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम को फुल टाइमर बॉस की कमी महसूस होती है। टीम को कई मुद्दों पर बातचीत करने की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि पार्ट टाइमर बॉस पूरा समय नहीं दे पाते हैं। आप अपनी कंपनी में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो यहां पर दिए जाने वाले टिप्स कारगर साबित हो सकते हैं। आइए डालते हैं एक नजर -

मानसिकता सही रखें

एक्सपर्ट कहते हैं कि एक पार्ट टाइमर बॉस किसी संस्था में काम करता है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों के मन में यह भावना विकसित हो सकती है कि

...तो आप भी हैं कामयाब लीडर

एक लीडर में अपनी बात को असरदार तरीके से दूसरों तक पहुंचाने का हुनर आना चाहिए। एक लीडर, अगर वह अपनी बात अपने साथ काम करने वालों को बेहतर तरीके से कम्प्यूनिकेट कर पाने में समर्थ है, तो इससे कामकाजी माहौल ऊर्जा से भर जाता है, लोग उत्साह से काम में जुटते हैं और उनकी रचनात्मकता काम में झलकने लगती है। एक दूरदर्शी सोच रखने वाला लीडर एक जुनूनी टीम बनाने में यकीन रखता है। यह टीम एक समान लक्ष्यों के लिए पूरे जोशखरोश से काम करती है। अपना कारोबार फैलाती किसी भी कंपनी को एक मजबूत मैनेजमेंट के साथ - साथ ऐसी टीम की भी दरकार रहती है, जो साथ काम करने वाले लोगों के बीच आपसी एकता, यकीन और आदर की बुनियाद पर बनी हो। कामयाबी का राज है, कामकाज में साफ - सुथरापन। एक कामयाब लीडर इस बात की अहमियत जानता है और अच्छे कामकाज के लिए अपने एंज्लोंई के साथ एक बेहतर समझ विकसित करता है। इससे न सिर्फ कामकाज का बिना किसी रुकावट के निपटारा होता जाता है, बल्कि टीम के भीतर एक खुशनुमा कामकाजी माहौल भी बरकरार रहता है।



इन बातों का ध्यान रखें तो कदम चूमेगी कामयाबी

जब आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं, तो यह जान जाते हैं कि आप कौन हैं? आप क्या हैं? आपको क्या करना है और आप क्या चाहते हैं? अगर ये चीजें आपके दिमाग में साफ हैं, तो आपकी सफलता का पहला चरण सुनिश्चित हो जाता है।

बनें योग्य

कामयाब होने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप खुद को योग्य बनाएं। क्योंकि आप तब तक ऊपर नहीं चढ़ सकते, जब तककि आप में योग्यता नहीं हो। इसलिए पहले खुद को योग्य बनाना जरूरी होता है। इसके लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। याद रखें कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है।

दबाव झेलने की क्षमता

जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो दबाव के साथ - साथ अवरोध भी उत्पन्न होगा। ऐसे में इस तरह की विपरीत परिस्थितियों को झेलने की क्षमता आपमें जरूर होनी चाहिए। वैसे जब आपको एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी हो तो रास्ते में दिक्कतें तो आएंगी ही।

दिक्कतों का सामना करने से ही सफलता का दरवाजा खुलता है।

भरपूर एकाग्रता जरूरी

इसके बिना तो आप साइकल भी नहीं चला सकते। एकाग्रता एक ऐसी चीज है, जो हर जगह काम आती है। आप अपने काम में इसके द्वारा ही परफेक्शन लाते हैं। किसी भी काम को साधारण से असाधारण बनाने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। इसके माध्यम से आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भेद सकते हैं।

रचनात्मकता भी जरूरी

एक प्रफेशनल की सफलता में उसकी रचनात्मकता का काफी अहम योगदान हो है। इसलिए इस ओर ध्यान देना जरूरी है।

साहस बनाए रखें

कहते हैं रिस्क लेने के बाद ही आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। इसके लिए साहस सबसे जरूरी चीज है। किसी ने सही कहा है कि हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती इसलिए जीतने के लिए साहस बहुत जरूरी है।



हार्डवेयर फील्ड में खूब हैं जॉब, मस्त सैलरी

आज शायद ही ऐसा कोई ऑफिस हो, जहां का कामकाज कंप्यूटर पर आधारित न हो। इसके अलावा, घर, स्कूल आदि जगहों पर भी सभी कामकाज कंप्यूटर पर ही किए जाते हैं। अगर ये सुचारु रूप से काम न करें, तो सारा कामकाज अचानक ठप हो सकता है। बैंकों और अन्य सरकारी कार्यालयों में नेटवर्क फेल होने की वजह से काम ठप रहने की खबरें आपने अक्सर पढ़ी होंगी, तब इस नेटवर्क को सही करने के लिए हार्डवेयर प्रफेशनल्स की ही मदद ली जाती है। नेटवर्किंग दरअसल कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर ऐसा जाल बनाने का फील्ड है जिसमें कोई संस्थान काम कर सके। कुल मिलाकर, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन से लेकर, इसकी मटेनेंस और रोजमर्रा के ऐडमिनिस्ट्रेशन तक का सारा जिम्मा कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट्स यानी हार्डवेयर इंजिनियर्स के जिम्मे होता है।

कोर्स

हार्डवेयर इंजिनियर बनने के लिए मुख्य रूप से दो बेसिक कोर्स करने पड़ते हैं। पहला, हार्डवेयर और दूसरा बेसिक नेटवर्किंग। हार्डवेयर रिलेटेड कोर्स से कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में तमाम तकनीकी जानकारी मिलती है। एक हार्डवेयर इंजिनियर या सिस्टम ऐडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए ये दोनों कोर्स करने बेहद जरूरी हैं। नेटवर्किंग में इससे आगे कोई एक्सपर्ट बनना हो, तो अपनी पसंद के हिसाब से कुछ और बेसिक कोर्स करने होंगे, जैसे - लेन (लोकल एरिया नेटवर्क) और वेन (वाइड एरिया नेटवर्क) से

जुड़े कोर्स। नेटवर्किंग से जुड़े कोर्स कराने के लिए कई सरकारी और प्राइवेट संस्थान हैं, जिन्होंने इन कोर्सेज के लिए अपनी अलग पहचान बनाई है। नेटवर्किंग सीखने के लिए तीन तरीके हैं - पहला ऑनलाइन स्टडी मटीरियल की मदद से खुद पढ़ाई, दूसरा ऐसे इंस्टिट्यूट्स जो किसी प्रोग्राम से जुड़े नहीं हैं और तीसरा सर्टिफाइड प्रोग्राम।

जॉब की कमी नहीं

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नेटवर्किंग में कोर्स करने के बाद कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, हेल्प डेस्क टेक्निशियन, नेटवर्क या सिस्टम ऐडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर सिक्वोरिटी



स्पेशलिस्ट के रूप में करियर बना सकते हैं। आज इन एक्सपर्ट्स की जरूरत लगभग हर संस्थान में होती है। फिर चाहे वह कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट हों, बैंक या अन्य सरकारी कार्यालय, कोई इंडस्ट्री या और कोई छोटी-बड़ी फर्म। जहां भी कामकाज कंप्यूटर आधारित है, वहां इन तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। सरकारें जिस तरह ई-गवर्नेंस पर जोर दे रही हैं, उससे यह फील्ड और भी हॉट बनता जा रहा है। इसके चलते स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क और डाटा सेंटर जैसे कई नए फील्ड खुल रहे हैं। कहा जा सकता है कि जब तक कंप्यूटर पर काम होता रहेगा, इन विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती रहेगी। ये किसी भी कंपनी के लिए नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम की देखभाल से लेकर, एंजलायीज और कस्टमर्स की तकनीकी जिज्ञासाओं को शांत करने तक का काम करते हैं। एंटी लेवल पर आपकी जिम्मेदारी केवल नेटवर्क और कंप्यूटर मटेनेंस की हो सकती है, लेकिन अनुभव के साथ आपको किसी कंपनी के लिए इंटरनेट आदि डिवेलप करने का जिम्मा भी दिया जा सकता है।

मनी मैटर्स

बरसों से आईटी फील्ड में अच्छी - खासी सैलरी रही है। हार्डवेयर प्रफेशनल्स के लिए सॉफ्टवेयर प्रफेशनल्स की तरह मौकों की कोई कमी नहीं है। एंटी लेवल पर आप 25 से 35,000 रुपये महीने की जॉब पा सकते हैं। अनुभव और समय के साथ इसमें बढ़ोतरी होगी।





मैडॉक फिल्मस के साथ काम कर रहे हैं इब्राहिम अली खान

सैफ अली खान के बेटे और अभिनेता इब्राहिम अली खान इन दिनों बहुत व्यस्त चल रहे हैं। उनके पास कई प्रोजेक्ट हैं। हाल ही में उनकी फिल्म सरजमीं रिलीज हुई है। इसके बाद उन्होंने दिलेर पर काम करना शुरू किया है। अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी बीटीएस तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें नजर आ रहा है कि वह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं। उन्होंने इन तस्वीरों के जरिए अपने फैंस को अपनी अगली फिल्म के बारे में अपडेट दी है। पोस्ट के मुताबिक दिलेर दिनेश विजान के मैडॉक फिल्मस के बैनर तले बन रही है। इसका निर्देशन कुणाल देशमुख कर रहे हैं। उन्होंने जन्नत और तुम मिले जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है।

पूरी हो गई दिलेर की शूटिंग

खबरों के मुताबिक दिलेर की शूटिंग इसी साल जनवरी में पूरी हुई है। फिल्म की शूटिंग चंडीगढ़, मुंबई, लंदन और कई दूसरी जगहों पर हुई है। कुणाल देशमुख की पत्नी सोनाली ने फिल्म पूरी होने पर कई तस्वीरें साझा की थीं। उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा दिलेर की शूटिंग पूरी हो गई। बहुत अच्छा सफर था।

श्रीलीला भी आएंगी नजर

फिल्म में इब्राहिम अली खान अहम किरदार में हैं। इसमें उनके साथ लीड रोल में साउथ की अभिनेत्री श्रीलीला हैं। फिल्म के बारे में बाकी जानकारी को गुप्त रखा गया है।



इब्राहिम अली खान का वर्कफ्रंट
इब्राहिम अली खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में कांयोज ईरानी की फिल्म सरजमीं में नजर आए थे। इसमें उनके साथ काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय किया है। फिल्म में उन्होंने एक आर्मी अफसर के बेटे का किरदार निभाया है। उन्हें आतंकवादी किडनेप कर लेते हैं और कई वर्षों के बाद छोड़ते हैं।



कॉकटेल 2 में हुई कृति सेनन की एंट्री

बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीकल आने वाला है। साल 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म में जहां दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी की तिकड़ी देखने को मिली थी, वहीं अब 'कॉकटेल 2' में नए चेहरों के साथ एक ताजा तड़का लगने जा रहा है। इस बार फिल्म की कमान संभाली है निर्देशक होमी अदजानिया ने और सबसे बड़ी खबर ये है कि कृति सेनन इस बार फिल्म की लीड अभिनेत्री होंगी।

होमी अदजानिया ने किया कन्फर्म

हाल ही में निर्देशक होमी अदजानिया ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कृति सेनन की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने कॉकटेल 2 का हैशटैग यूज किया। इसके साथ ही उन्होंने वर्क इन प्रोग्रेस भी लिखकर इस बात का संकेत दिया कि फिल्म की तैयारियां अब ज़ोरों पर हैं। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, क्योंकि अभी तक फिल्म से जुड़ी कोई आधिकारिक कार्टिंग अनाउंसमेंट सामने नहीं आई थी। लेकिन अब कृति की फिल्म में एंट्री का ऐलान हो चुका है।

क्या होगी नई कॉकटेल की कहानी?

फिल्म की कहानी को लेकर काफी गोपनीयता बरती जा रही है। हालांकि सूत्रों की मानें तो इस फिल्म में मॉडर्न रिश्तों और आधुनिक प्यार की एक नई परत को उजागर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि फिल्म में कृति सेनन के साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना मुख्य

भूमिकाओं में होंगे। ये तिकड़ी पहले कभी साथ नहीं दिखी और ऐसे में इन तीनों की केमिस्ट्री दर्शकों के लिए एक नया अनुभव बन सकती है।

शूट से पहले ही रश्मिका ने भी बतोरी सुर्खियां

हाल ही में रश्मिका मंदाना ने भी निर्देशक होमी की एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अपनी एक मजेदार तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा वर्क इन प्रोग्रेस और चेहरा छिपा रखा था। यह संकेत था कि वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, हालांकि उन्होंने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।



फिर शाहिद और कृति की जोड़ी

कृति सेनन और शाहिद कपूर पहले 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में साथ नजर आ चुके हैं और अब इस नई फिल्म में एक बार फिर इनकी जोड़ी दर्शकों को देखने को मिलेगी। पिछली फिल्म में इनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को सराहा गया था, ऐसे में 'कॉकटेल 2' से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्मस के बैनर तले किया जा रहा है और इसकी पटकथा लिखी है लव रंजन ने। बताया जा रहा है कि फिल्म साल 2026 के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कृति के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

कृति के फैंस के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं, क्योंकि वो पहले ही धनुष के साथ 'तेरे इश्क में' और रणवीर सिंह के साथ 'डॉन 3' जैसी बड़ी फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं। अब 'कॉकटेल 2' उनकी फिल्मी लिस्ट में एक और दमदार नाम जोड़ता है।

झांसी की रानी का किरदार निभाकर मुझे एक नया जन्म मिला

भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना ने शिरडी साई बाबा के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म मणिकर्णिका - द क्वीन ऑफ झांसी में झांसी की रानी का रोल निभाने को लेकर अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में झांसी की रानी का रोल निभाकर उन्हें एक नया जन्म मिला। वह झांसी की रानी फिल्म से पुनर्जीवित हुईं। फिल्म इंडस्ट्री में जो मेरी इमेज खराब कर रखी थी, उसमें भी परिवर्तन आया। कंगना रनौत ने आगे कहा कि इस फिल्म के जरिए उन्हें देश और आजादी के संघर्ष के बारे में जानने को मिला। स्कूल में छोटे-छोटे बच्चे झांसी की रानी पर कार्यक्रम करते हैं और झांसी की रानी का किरदार निभाते हैं तो यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। हमारी वीरांगनाओं पर और फिल्म बननी चाहिए।



निधि अग्रवाल ने रोमांचक फिल्म की घोषणा के साथ मनाया जन्मदिन

साउथ एक्ट्रेस निधि अग्रवाल ने अपनी कुछ ही फिल्मों से दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली है। उनके जन्मदिन पर द राजा साहब के निर्माताओं ने उनका कैरेक्टर पोस्टर जारी कर उन्हें जन्मदिन की ख़ास बधाई दी है। निर्माताओं ने निधि की ख़ास तस्वीर इंस्टाग्राम हैडल पर शेयर की और कैप्शन में लिखा, उसकी आंखों में राज है, उसकी मौजूदगी सिहरन पैदा करती है, पर चेहरा अनदेखा रहता है। इस दशहरा पर, अंधेरे को नाम मिल गया है, उसके खुलासे का इंतजार है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्योति क्रिएशन्स ने अपनी पहली फिल्म में निधि को मुख्य भूमिका में लेने की घोषणा की है। इस फिल्म का नाम दशहरा के मौके पर बताया जाएगा। फिल्म के

निर्माता पुष्पाला अप्पाला राजू हैं और इसे निखिल कार्तिक एन ने लिखा और निर्देशित किया है। निधि अग्रवाल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। उन्होंने 2017 में मुग्धा माइकल से बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके लिए जी सिने अवॉर्ड जीता। इसके बाद 2018 में तेलुगु फिल्म स्वयंसाची और 2021 में तमिल फिल्म ईश्वरन से तेलुगु और तमिल सिनेमा में कदम रखा। निधि जल्द ही प्रभास की फिल्म द राजा साब में नजर आएंगी।



मिर्जापुर द फिल्म में जितेंद्र कुमार के साथ रवि किशन की भी हुई एंट्री

पॉप्युलर वेब सीरीज मिर्जापुर के चौथे सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार रवि किशन और जितेंद्र कुमार भी कलाकारों के साथ जुड़ गए हैं, हालांकि उनके किरदार अभी तक गुप्त रखे गए हैं। मिर्जापुर द फिल्म, जिसका निर्देशन गुरमीत सिंह कर रहे हैं, 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है। पॉप्युलर वेब सीरीज मिर्जापुर के अगले सीजन के लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अब तक तीन सीजन आ चुके हैं और चौथे सीजन को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। जहां अली फजल और पंकज त्रिपाठी के किरदारों की धड़पक दर्शकों को एक बार फिर से एंटरटेन करेगी। वहीं, इस बार रवि किशन और जितेंद्र कुमार भी उनका साथ देंगे। हालांकि उनका क्या रोल होगा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मिर्जापुर द फिल्म से जुड़े एक सॉर्स ने बताया है, जितेंद्र और रवि किशन फिल्म की कास्ट में शामिल हो गए हैं। फिल्म की मुहूर्त पूजा गुरुवार, 14 अगस्त को हुई और वो दोनों ही इसमें मौजूद थे। उनके किरदारों को फैंस के लिए एक बड़े सरप्राइज के तौर पर रखा जा रहा है। कलाकारों के लुक टेस्ट और सीडिंग सेशन शुरू हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगे। जितेंद्र और रवि भी प्री-प्रोडक्शन के काम में शामिल हो गए हैं। फिल्म अगले महीने पत्तों पर जाएगी।

पोर्टल ने जब रवि किशन से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने इस बारे में बात करने से मना कर दिया और जितेंद्र की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं मिला। लेकिन पुरानी रिपोर्ट्स में बताया गया था कि जितेंद्र कुमार को विक्रांत मैसी की जगह कास्ट किया गया है और वह लीड रोल में दिखाई देंगे। और बबलू पंडित का रोल निभाएंगे। हालांकि मेकर्स ने कुछ कंफर्म नहीं किया है। 2024 में ही इसके चौथे सीजन की अनाउंसमेंट कर दी गई थी। अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंद्र का एक वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था।

मिर्जापुर द फिल्म की रिलीज डेट

पुनीत कृष्णा की प्रोड्यूसर और गुरमीत सिंह की डायरेक्टड मिर्जापुर द फिल्म अगले साल 2026 में रिलीज होगी। अमेजन प्राइम वीडियो पर ये पूरे देशभर में देखी जा सकेगी। बताया जा रहा है कि श्वेता त्रिपाठी का इसमें कमेंबैक हो सकता है, जिनकी तीसरी सीजन में जान जाते हुए दिखाया गया था। साथ ही पंकज त्रिपाठी का वफादार नौकर भी बदला लेने के लिए लौटेगा।

जवाब में वह कहते हैं, हमारी ये फिल्म इंडिया-पाकिस्तान के बीच हुई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, इसमें हमने दो देशों के मुद्दे को जबरन नहीं डाला। ये एक सच्चे जासूस की कहानी है, जहां 1978 के जमाने में देश के लिए लड़ा था। ये भारत के अनसंग हीरोज की कहानी है।

देशभक्ति का पाठ घर में पढ़ाया गया है

फारुक कबीर की फिल्मोग्राफी पर अगर नजर डाली जाए, तो उनका देश भक्ति से ओतप्रोत फिल्मों की ओर ज्यादा झुकाव रहता है। उनकी पिछली फिल्में खुदा हाफिज और खुदा हाफिज 2 भी उसी तर्ज पर थीं और अब सलाकार भी एक देशभक्ति से लबरेज स्पॉइड ब्रामा है। वह कहते हैं, मैं अपनी जमीन को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। एक जमाने में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, जिसमें मैं बाई रोड 27,000 किलोमीटर पूरा इंडिया घूमा था और उसी के बाद मैं अपने देश की मिट्टी ही नहीं, इसके पहलुओं और लोगों को भी बहुत करीब से जान पाया। मेरी उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम था, अन्हर्ड वॉइसेज ऑफ इंडिया मैंने पाया कि देशभक्ति इंडिया-पाकिस्तान के मैच से कहीं बहुत ज्यादा ऊंची और परे है।

मुझे देशभक्ति विरासत में मिली, मेरे दादा आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए थे

फिल्मी खानदान से तात्त्विक रखने वाले फारुक कबीर के लिए इंडस्ट्री में अपनी जमीन तलाशना आसान नहीं था। अल्लाह के बटे जैसी चर्चित फिल्म से निर्देशक बने फारुक कबीर अशोका और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में सहायक निर्देशक भी रहे। उन्होंने अवॉर्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री अनहर्ड वॉइसेज ऑफ इंडिया भी बनाई। खुदा हाफिज वन और खुदा हाफिज टू के बाद वह इन दिनों ओटीटी की नई सीरीज सलाकार के कारण चर्चा में हैं।

बचपन से ही फिल्मी माहौल में पले-बढ़े फारुक कबीर अपनी पृष्ठभूमि के बारे में कहते हैं, मैं अपने करियर और जीवन में अपनी मम्मी से काफी प्रभावित रहा हूँ। मेरी मम्मी सबीहा कॉस्ट्यूम डिजाइनर हुआ

करती थीं लंबे समय तक। शर्मिला टैगोर, पद्मिनी कोल्हापुरे, मीनाक्षी शेषादि, फरहा, तब्बू, नीलम, माधुरी दीक्षित और किमी काटकर जैसी कई एक्ट्रेस के लिए वह कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थीं। मुझे लगा कि मेरी मां अगर इतने साल तक मेहनत करके हमें पाल-पोसकर किसी काबिल बनाती हैं, तो फिर मुझे तो उनके नाम को रोशन करना ही है। यही वजह थी, जो मैंने भी फिल्मी दुनिया को चुना। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका और प्यार इश्क और मोहब्बत जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक रहे फारुक कबीर, उस दौर के अपने अनुभव के बारे में कहते हैं, शाहरुख (खान) भाई से मैंने विनम्रता और कड़ी मेहनत करना सीखी। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे अजीज मिर्जा और संतोष सिवान जैसे फिल्मकारों की सोहबत मिली, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उस वक्त मैं मात्र 18 साल का था। इन फिल्मकारों से मैंने सीखा कि राइटिंग और स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी होती है। इंडिपेंडेंट निर्देशक बनने का सफर काफी मुश्किल रहा

सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके फारुक ने अमेरिका जाकर राइटिंग का डिप्लोमा भी लिया। वह अपने सफर के बारे में कहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का मेरा सफर आसान नहीं था। मैंने काफी संघर्ष किया, मेरी स्क्रिप्ट को कई बार नकारा गया, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी क्षमता में कोई कमी है। पूरे दस साल बाद आई मेरी खुदा हाफिज और उसके बाद खुदा हाफिज 2...अब हाल ही सीरीज सलाकार आई है, जिसकी कहानी को संजीदगी से कहना जरूरी था। मैंने 6 महीने तक ये स्क्रिप्ट लिखी। ये सीरीज लिखना इसलिए चुनौतीपूर्ण था कि ये एक पीरियड ड्रामा है और 1978 का माहौल दर्शाना आसान नहीं था। हमने इसमें दो टाइमलाइन रखी हैं। एक आज की और एक तब की।

भारत-पाकिस्तान के मुद्दे पर क्यों होती हैं ज्यादातर भारतीय फिल्में?

मगर हमारी ज्यादातर फिल्में इंडिया-पाकिस्तान के मुद्दे के इर्दगिर्द ही क्यों होती हैं? इस सवाल के

